www.dhyeyaias.com

अप्रैल 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 पर्यावरण संरक्षण का बेहतर उपाय
ग्रीन बिल्डिंग

2 कोविड-19 महामारी से वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र का बदलता स्वरूप

3 अमेरिका द्वारा डब्ल्यूएचओ फंड का निलंबन और उसका प्रभाव

4 अर्थोपाय अग्रिम : आरबीआई के तरलता प्रबंधन का उपकरण

5 भारत में इमरजेंसी बेसिक इनकम की व्यवहार्यता

6 स्वच्छता कार्यकर्ता : कोविड-19 के विरूद्ध पहली पंक्ति के योद्धा

7 कोविड-19 महामारी बनाम सतत् विकास लक्ष्य

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं. **+91-11-2397 8046** पर कॉल करें या ई-मेल करें **ncov2019@gmail.com**

mohfw.gov.in | @MoHFWIndia | @MoHFW_INDIA | mohfwindia

ध्येय IAS
एक परिचय

विनय कुमार सिंह

संस्थापक एवं सीईओ

ध्येय IAS

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान

प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect7

एक परिचय

कुरबान अली

प्रधान संपादक

ध्येय IAS

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **'PERFECT 7'** का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरूआत से ही **ध्येय IAS** द्वारा प्रकाशित **'PERFECT 7'** को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaias.com और यूट्यूब चैनल देखें।

आशुतोष सिंह

प्रबंध सम्पादक

ध्येय IAS

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम **'PERFECT 7'** रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें **'PERFECT 7'** के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंतत: उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर **'PERFECT 7'** को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब **'PERFECT 7'** अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान मे रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर **'PERFECT 7'** के रंगीन संस्करण की शुरूआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही **ध्येय IAS** से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ अंशुमान तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ स्नेहा तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ विपिन सिंह ➢ कृष्ण कुमार ➢ निखिल ➢ रमेश कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अप्रैल 2020 | अंक 04

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- पर्यावरण संरक्षण का बेहतर उपाय : ग्रीन बिल्डिंग
- कोविड–19 महामारी से वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र का बदलता स्वरूप
- अमेरिका द्वारा डब्ल्यूएचओ फंड का निलंबन और उसका प्रभाव
- अर्थोपाय अग्रिम : आरबीआई के तरलता प्रबंधन का उपकरण
- भारत में इमरजेंसी बेसिक इनकम की व्यवहार्यता
- स्वच्छता कार्यकर्ता : कोविड–19 के विरुद्ध पहली पंक्ति के योद्धा
- कोविड–19 महामारी बनाम सतत् विकास लक्ष्य

7 ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–26

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 27

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 28

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ 29

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. पर्यावरण संरक्षण का बेहतर उपाय : ग्रीन बिल्डिंग

चर्चा का कारण

- हाल ही में 50वें पृथ्वी दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हम सभी को प्रकृति सम्मत विकास पर बल देना होगा। इसके लिए हम पर्यावरण सम्मत ग्रीन बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा स्रोत, प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकी आदि को अपना सकते हैं।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के अनुभव के बाद हमें अपनी विकास और आर्थिक नीतियों की नये सिरे से दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए ग्रीन बिल्डिंग जैसी विकास की नयी अवधारणाओं को अपनाया जा सकता है।

ग्रीन बिल्डिंग

- ग्रीन बिल्डिंग (हरित इमारत), उस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसके डिजाइन से लेकर निर्माण एवं रख-रखाव तक में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन इमारतों से पर्यावरण क्षति न्यून हो जाती है।
- ग्रीन बिल्डिंग में फ्लाई ऐश (Fly Ash) से बनी ईटों, हाई इनर्जी कन्जर्वेशन लैम्प, वाटर रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे फीचर का इस्तेमाल किया जाता है।
- ग्रीन बिल्डिंग में पानी के रिसाइक्लिंग पर काफी अधिक ध्यान दिया जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए वर्षा के जल की हार्वेस्टिंग की जाती है। इस्तेमाल होने वाले पानी की वापस रिसाइक्लिंग करके उपयोग में लाया जाता है।
- ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण सूर्य की रोशनी को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि बिल्डिंग के अन्दर सूर्य का प्रकाश तो मिले किन्तु उसका तापमान न बढ़े। इससे दिन में लाइट्स जलाने की जरूरत कम पड़ती है, साथ ही एयर कंडीशनर की भी जरूरत कम पड़ती है। इस तरह से बिजली की खपत बहुत कम हो जाती है।
- ग्रीन बिल्डिंग में प्राकृतिक हवा के प्रवेश और निकासी की बेहतर डिजाइनिंग होती है। ताकि पंखा, कूलर आदि की कम से कम आवश्यकता हो।
- फ्लाई ऐश की ईटें या टाइल्स अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। गर्मियों के दिनों में जब बिल्डिंग की बाहरी दीवारें गर्म हो जाती हैं तो फ्लाई ऐश अन्दरूनी भाग को ठण्डा बनाये रखती है।
- ग्रीन बिल्डिंग में सीवरेज ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
- ग्रीन बिल्डिंग की बालकनी, खिड़की, गैलरी, छत और ओपेन टैरेस में गमले आदि रखने की जगह छोड़ी जाती है ताकि लोग छोटे-छोटे पेड़-पौधों को इसमें लगा सकें।
- ग्रीन बिल्डिंग के आस-पास पेड़-पौधे भी लगाये जाते हैं ताकि उस क्षेत्र का तापमान कम और वायु स्वच्छ रहे।

ग्रीन बिल्डिंग के लाभ

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, ग्रीन बिल्डिंग एक साधारण इमारत के अपेक्षाकृत 30 से 40 प्रतिशत बिजली और 30 से 70 प्रतिशत जल की बचत करती है।
- प्राकृतिक ऊर्जा के उपयोग के कारण ग्रीन बिल्डिंग में रहने वालों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत बेहतर रहता है।
- ग्रीन बिल्डिंग के द्वारा संसाधनों का धारणीयता के साथ उपयोग संभव होता है।

ग्रीन बिल्डिंग की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान में पृथ्वी का तापमान धीरे-धीरे लगातार बढ़ रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं ने जन्म लिया है। इसके अतिरिक्त, ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्र जल-स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ खाद्य संकट भी उत्पन्न किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग के द्वारा भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है।
- आज वैश्विक स्तर पर मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है जिसके कारण मानव आवास हेतु जंगलों को काटा जा रहा है। प्रकृति के बेतरतीब क्षरण ने कोविड-19 जैसी महामारियों को भी न्योता दिया है। ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण सम्मत होती हैं और प्राकृतिक संरक्षण पर बल देती हैं, अतः इनके द्वारा मानव गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से बच सकता है।
- भारत ने लक्ष्य रखा है कि वह सन् 2005 की तुलना में अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक की कमी लायेगा। इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने हेतु भारत में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण की अति आवश्यकता है।
- भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी है और 2050 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है। भारत में 70 प्रतिशत

ऐसी इमारतें (यथा-आवास, वाणिज्यिक, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि) हैं जिनका निर्माण 2030 तक पूर्ण हो पायेगा, इसलिए भारत के पास वर्तमान में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का सुनहरा अवसर है।

चुनौतियाँ

- **सीमित जागरूकता:** आज भी, भारतीय उपयोगकर्ताओं का बड़ा वर्ग ग्रीन बिल्डिंग के स्थायी लाभों से अनजान है। उन्हें ग्रीन बिल्डिंग मंहगा और वित्तीय रूप से अक्षम विकल्प लगता है।
- **अपर्याप्त नीतियाँ:** ग्रीन बिल्डिंग के निर्धारित मानदण्डों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए उपयुक्त नीति एवं कानून नहीं है।
- **अपर्याप्त प्रोत्साहन:** सरकार की तरफ से ग्रीन बिल्डिंग को बहुत कम प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि विभिन्न राज्यों की सरकारें ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण पर सम्पत्ति कर (Property Tax) आदि में छूट देती हैं, जोकि अपर्याप्त है।
- **निवेश:** ग्रीन बिल्डिंग क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही निवेश कम होता है।
- **विशेषज्ञों की कमी:** भारत में रियल स्टेट क्षेत्र के अधिकांश हितधारक (यथा-नीति निर्माता, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, श्रमिक आदि) ग्रीन बिल्डिंग के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखते हैं।

ग्रीन बिल्डिंग नियामक ढाँचा

- ग्रीन बिल्डिंग के लिए भारत में अब धीरे-धीरे नियामक ढाँचा विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय भवन संहिता (2016), जो भारत में निर्माण (Construction) गतिविधियों को नियंत्रित करती है, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा विकसित ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) भी शामिल करती है।
- ग्रीन बिल्डिंग के प्रमाणन और रेटिंग प्रणाली भी भारत में विकसित हो रही है। बीईई बिल्डिंग स्टार रेटिंग सिस्टम, इमारतों को उनकी ऊर्जा दक्षता के आधार पर मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त भारत में दो अन्य ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम हैं-(i) ग्रिहा (GRIHA) (ii) आईजीबीसी।
- एकीकृत आवास आकलन की ग्रीन रेटिंग (Green Rating for Integrated Habitat Assessment-GRIHA) प्रणाली को टेरी (TERI) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

वाणिज्यिक बैंक और एनबीएफसी

- बैंक और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) उन बिल्डिरों को रियायत दर पर ऋण प्रदान करें जो ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में संलग्न हैं, इससे ग्रीन बिल्डिंग क्षेत्र में निजी निवेश भी आयेगा।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत आवासीय ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Primary Sector Lending-PSL) की श्रेणी में आते हैं, इसमें ग्रीन बिल्डिंगों के निर्माण हेतु एक और प्राथमिकता वाली उप श्रेणी बनायी जा सकती है।

ग्रीन बॉण्ड (Green Bond)

- ग्रीन बॉण्ड के तहत प्राप्त होने वाले धन को ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ग्रीन बॉण्ड के तहत प्राप्त धन को जारीकर्ता (Issuer) सिर्फ पर्यावरण सम्मत योजनाओं में लगा सकते हैं। ग्रीन बॉण्ड भी अन्य नियमित बॉण्ड की ही तरह होते हैं। यस बैंक ने सर्वप्रथम पहली बार ग्रीन बॉण्ड जारी किये थे (सन् 2015 में)। इसके बाद कुछ अन्य बैंकों ने भी ग्रीन बॉण्ड जारी किये थे।

आगे की राह

- ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण संरक्षण के लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं, अत: सरकार को इनके विकास हेतु उपयुक्त नीति बनानी चाहिए जिसमें लघुकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लक्ष्य होने चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. ग्रीन बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं? भारत में ग्रीन बिल्डिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों की चर्चा करने के साथ-साथ इनके विकास हेतु सुझाव भी दें।

2. कोविड-19 महामारी से वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र का बदलता स्वरूप

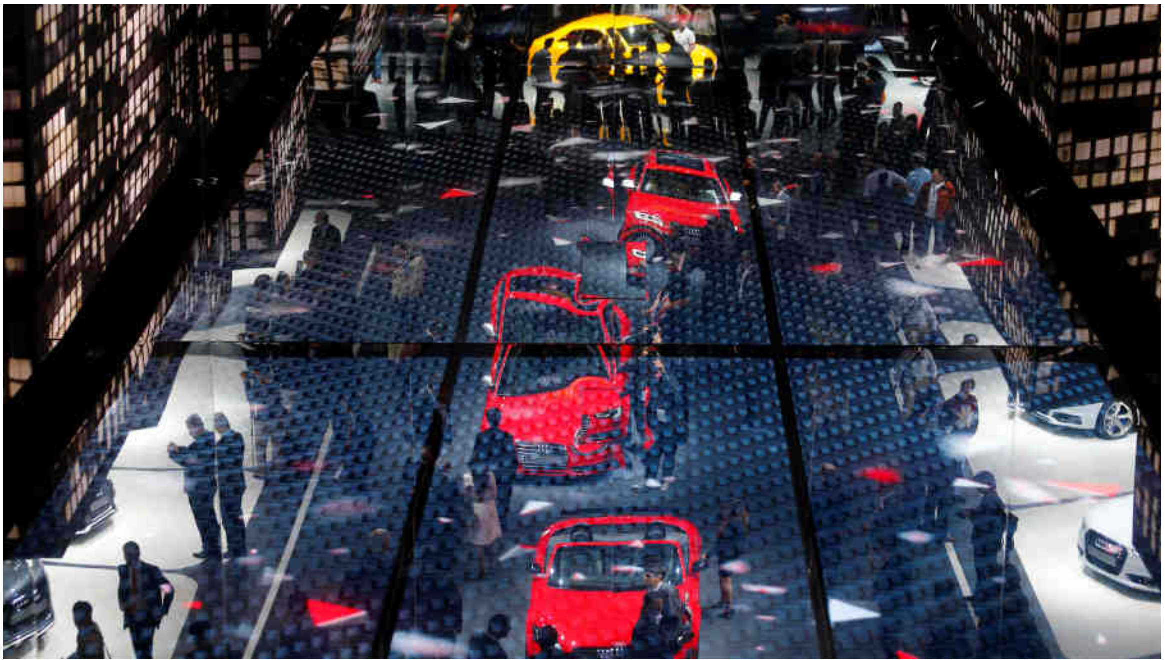

चर्चा का कारण

- वर्तमान में पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है और लगभग प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला (Global Value Chain) में विनिर्माण गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ के साथ गहरे बदलाव आ रहे हैं।

परिचय

- मानव के लिए कोरोना वायरस का खतरा तभी मिट सकता है जब इसके लिए कोई वैक्सीन का निर्माण हो जाये। जब तक इस वायरस से निपटने हेतु वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पा रहा है तब तक आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पायेंगी।
- इस समय विश्व में एशिया के देश अपेक्षाकृत अधिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कई देश (यथा-चीन, भारत आदि) वैश्विक आपूर्ति शृंखला में विनिर्माण के प्रमुख केन्द्र हैं। एशिया के इन देशों में अपेक्षाकृत सस्ता एवं कुशल श्रम मौजूद है, इसी कारण विश्व की अधिकतर कम्पनियों ने यहाँ अपनी उत्पादन इकाईयाँ स्थापित की है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने एक आकलन में कहा है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ ने भारतीय जीडीपी की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.9% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
- विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 11 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं। महामारी को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया हुआ है जो विनिर्माण एवं उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, इससे लोगों के रोजगार छिन रहे हैं।
- भारत, बांग्लादेश, वियतनाम आदि जैसे देशों में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की भरमार है जो श्रम गहनता के लिए जाने जाते हैं, किन्तु देश एवं विदेश में माँग कम होने एवं लॉकडाउन के कारण श्रम गतिशीलता में भारी कमी होने से इन उद्योगों में उत्पादन गतिविधियाँ बहुत कम हो गयी हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा किये गये एक विश्लेषण के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने वैश्विक विनिर्माण उत्पादन को सबसे अधिक प्रभावित किया है क्योंकि महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ा है।

वैश्विक विनिर्माण और प्रौद्योगिकी

- विभिन्न क्षेत्र के उद्योगों ने उत्पादों के विनिर्माण हेतु अब प्रौद्योगिकियों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग प्रारम्भ कर दिया है, यथा-रोबोट, कृत्रिम बौद्धिकता, 3D-प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, कटिंग-एज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि।
- कोविड-19 महामारी के चलते विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन लगाया गया है, इसके कारण श्रम की गतिशीलता में भारी कमी आयी है; अतः इस कमी को पाटने हेतु रोबोट (Robot) के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति उन औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है जिनके उत्पादों की माँग वर्तमान में काफी अधिक है।
- दवा से लेकर मेडिकल क्षेत्र के प्रत्येक उपकरण, रसायन, सैनिटाइजर, मॉस्क एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भारी माँग है जिसके कारण इस क्षेत्र के उद्योग रोबोट, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस आदि पर अधिक ध्यान दे रहे हैं ताकि उत्पादन को अधिक से अधिक करके माँग और पूर्ति के संतुलन को साधा जा सके।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट के उपयोग द्वारा कम्पनियाँ 'वर्क फ्रॉम होम' (Work From Home) की संस्कृति को अपना रही हैं।

प्रौद्योगिकी के लाभ

- रोबोट जैसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने से उत्पादन एक-साथ काफी मात्रा में हो सकता है।

- प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादन को काफी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है अर्थात् माँग के अनुसार उत्पादन को घटाया-बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि श्रमिकों द्वारा उत्पादन को अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि एक-साथ अचानक कई श्रमिकों की नियुक्ति करना संभव नहीं है। इसी प्रकार उत्पादन को अचानक घटाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि इससे बेरोजगारी का संकट पैदा हो सकता है।
- विनिर्माण में मशीनों (अर्थात् प्रौद्योगिकी) के इस्तेमाल से कम्पनियाँ श्रमिकों देने को वाले विभिन्न सामाजिक लाभों (यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) और कड़े श्रम कानूनों से बच सकती हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो सकती है।
- मशीनों के द्वारा उत्पादित वस्तुएँ अपेक्षाकृत सस्ती और ज्यादा संपूर्ण (Finished) होती हैं और 3D प्रिंटिंग आदि के द्वारा इनकी डिजाइनिंग भी आसान हो जाती है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के द्वारा 'वर्क फ्रॉम होम' संस्कृति को बढ़ावा देकर कोविड-19 महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जब प्रौद्योगिकी इकाईयों में रोबोट आदि के द्वारा उत्पादन होगा तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी कम हो जायेगा। यही कारण है कि अस्पतालों में वर्तमान में कई रोबोट निदान और उपचार (Diagnosis and Treatment) गतिविधियों में संलग्न हैं।
- जब प्रौद्योगिकी के द्वारा गतिविधियों को अधिक सम्पन्न किया जायेगा तो इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

- भले ही प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन गतिविधियों को तीव्र एवं आसान किया जा सकता है किन्तु इसके कई हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। मशीनीकरण के बढ़ने के परिणास्वरूप बड़ी मात्रा में लोगों के रोजगार छिन सकते हैं। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो उनकी आय प्रभावित होगी जो अर्थव्यवस्था में माँग को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में माँग के न होने से, उसका लम्बे समय तक टिकाऊ बने रहना मुश्किल है।
- विभिन्न कम्पनियाँ 'वर्क फ्रॉम होम' कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं, किन्तु इससे सम्बन्धित समस्या यह है कि भारत जैसे विकासशील देशों में डिजिटल इन्फ्रॉस्ट्रक्चर अभी कमजोर स्थिति में है, अतः 'वर्क फ्रॉम होम' का यहाँ अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम है।
- विनिर्माण में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से एमएसएमई क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन छोटे उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी में निवेश हेतु वित्त की कम मात्रा होती है।

वैश्विक विनिर्माण केन्द्र

- कोविड-19 महामारी से पहले चीन, वैश्विक विनिर्माण का केन्द्र था। लेकिन कोविड-19 महामारी की शुरूआत चीन से हुई, जिसके कारण चीन में आर्थिक गतिविधियाँ कम हो गयीं। कई कम्पनियाँ ने यहाँ अपनी औद्योगिक इकाईयों को बंद कर दिया। परिणामस्वरूप पूरे विश्व में दवा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गयी।
- विश्व बिरादरी ने विनिर्माण केन्द्रों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता को गहराई से महसूस किया है। कई वैश्विक कम्पनियों ने अब इन देशो की ओर रूख किया है जो चीन का विकल्प हो सकते हैं, यथा-भारत आदि।

आगे की राह

- कोविड-19 महामारी एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटने हेतु सभी को एक-साथ मिलकर प्रयास करना होगा।
- वैश्विक नेतृत्व को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उचित विनिर्माण नीति को प्रोत्साहित करना होगा। इस नीति में वस्तुओं के उत्पादन के साथ-साथ लोगों के रोजगार पर भी ध्यान देना अति महत्त्वपूर्ण है।
- वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है किन्तु प्रौद्योगिकी का उपयोग ऐसे होना चाहिए जिससे कि मानव हित साधे जा सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

प्र. कोविड-19 महामारी के दौर में वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का अलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

3. अमेरिका द्वारा डब्ल्यूएचओ फंड का निलंबन और उसका प्रभाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 को मानवता का खतरनाक दुश्मन बताते हुए उससे निपटने में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की अहमियत को दोहराया है। उन्होंने अमेरिका के उस निर्णय पर खेद जताया है जिसमें यूएन स्वास्थ्य एजेंसी को दी जाने वाली धनराशि तब तक रोके जाने की बात कही गई है जब तक महामारी फैलने के शुरुआती चरण में एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती है।

मामला क्या है

- कोरोना वायरस महामारी ने दुनियाभर में जो तबाही मचाई है, उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर हमलावर हैं। इसी के साथ उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का साथ देने, कोरोना वायरस की बात छुपाने का आरोप लगाया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि, 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई मौकों पर अमेरिका के साथ भेदभाव किया है, ऐसे में वो हमपर राजनीति करने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। विदित हो कि चीन WHO को सिर्फ 42 मिलियन देता है, लेकिन अमेरिका 450 मिलियन की मदद देता है।
- इसके बावजूद सब कुछ चीन के हक में ही जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी लंबे समय से कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसे चीनी वायरस कहते हैं।
- ट्रंप का आरोप है कि चीन की गलती को WHO ने छुपाया, जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। विदित हो कि अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से लगभग 8.5 लाख से अधिक लोग बीमार हैं, जबकि लगभग 46 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में करीब 10 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना क्यों हो रही है

- अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर जिम रिच ने कोविड-19 से निपटने में डब्ल्यूएचओ के तौर तरीकों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ न केवल अमेरिकी लोगों के लिए नाकाम हुआ बल्कि वह कोविड-19 से निपटने में घोर लापरवाही के साथ विश्व के मोर्चे पर भी नाकाम हुआ।
- डब्ल्यूएचओ से यह उम्मीद की जाती है कि वह स्वास्थ्य संबंधी किसी भी खतरे को लेकर समय रहते दुनिया को जानकारी दे। किन्तु कोविड-19 महामारी के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
- डब्ल्यूएचओ अपने मूल कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा है। इसके लिए उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

डब्ल्यूएचओ का पक्ष

- जब से चीन के वुहान प्रान्त में कोविड-19 बीमारी उभरी है, और किसी अज्ञात कारण से हुए न्यूमोनिया के पहले मामले की खबर पिछले वर्ष 31 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई थी, तब से यूएन स्वास्थ्य एजेंसी आँकड़ों का विश्लेषण करने, परामर्श देने, साझीदारों के साथ तालमेल बिठाने, और तैयारी में देशों की मदद करने में रात दिन काम कर रही है। जानकारी मिलने के लगभग एक महीने बाद डब्ल्यूएचओ द्वारा इस बीमारी को अंतरराष्ट्रीय चिन्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अधिकारियों ने चीन केंद्रित होने के ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि दुनिया जब कोरोना से लड़ रही है तो ऐसे समय में फंड कम करना उचित नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ चीफ ने भी अमेरिका और चीन से अपील की कि वे कोरोना वायरस महामारी से मिलकर निपटें। डब्ल्यूएचओ ने साथ ही कहा कि अंतरराष्ट्रीय एकता के बिना कोरोना वायरस को नहीं हराया जा सकता।
- अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 महामारी दुनिया की एक ऐसी बेहद खतरनाक चुनौती है जिसका सामना हम अपने जीवनकाल में पहली बार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह एक मानवीय संकट है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक नतीजे जुड़े हैं।
- महासचिव गुटेरेश ने कहा है कि यह समय यूएन स्वास्थ्य एजेंसी या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटी अन्य किसी मानवीय राहत एजेंसी के संसाधनों में कटौती करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता दिखाने का है ताकि वायरस और उसके विनाशकारी नतीजों को रोका जा सके।
- यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाया है कि हजारों की संख्या में यूएन एजेंसी के कर्मचारी वास्तविक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, तथा अग्रिम मोर्चों पर वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटे हैं एवं सदस्य देशों को समर्थन दे रहे हैं, साथ ही बेहद नाजुक हालात में रहने के लिए मजबूर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यूएन एजेंसी से दिशानिर्देश, ट्रेनिंग, उपकरण और ठोस जीवन-रक्षक सहायता मिल रही है।
- यूएन प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि जब दुनिया इस महामारी को काबू में कर लेगी तो वह समय भी आएगा जब यह पता लगाया जा सकेगा कि किस तरह यह बीमारी उभरी और दुनिया भर में इससे इतनी जल्दी तबाही कैसे फैल गई, और जो पक्ष इससे निपटने की कार्रवाई में शामिल थे उन्होंने किस तरह से कदम उठाए।

डब्ल्यूएचओ

डब्ल्यूएचओ (संयुक्त राष्ट्र का निकाय) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गयी थी। यह सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और फिलहाल 150 देशों में लगभग 7,000 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं।

अमेरिका के निधि रोकने का संभावित प्रभाव एवं वैश्विक प्रतिक्रिया

- कई जानकारों ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि इस वक्त जब विश्व स्वास्थ्य संगठन को अधिक वित्तीय मदद की जरूरत है ,अमेरिका अपने योगदान पर रोक लगाकर ठीक नहीं कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस वक्त स्वास्थ्य संगठन के काम में बाधा पहुंचेगी, तो कोई दूसरा संगठन उसकी जगह नहीं ले पाएगा।
- बिल गेट्स और माइकल ब्लूमबर्ग जैसे परोपकारियों ने यूरोपीय और अफ्रीकी नेताओं तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए डब्लयूएचओ का पक्ष लिया और जोर दिया कि अमेरिका को संकट के समय में वित्त पोषण नहीं रोकना चाहिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रमुख बिल गेट्स डब्ल्यूएचओ में सबसे बड़े स्वैच्छिक और गैर-राष्ट्र दानकर्ता हैं। उन्होंने ट्रंप द्वारा फंडिंग रोके जाने को खतरनाक बताया है।
- यूरोपीय संघ (ईयू) ने कहा है कि इस नाजुक घड़ी में डब्ल्यूएचओ को वित्तीय अनुदान रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का कोई कारण नहीं है। साथ ही, विभाजन के बजाय एकजुटता को प्रोत्साहित करने के कदम उठाने की भी अपील की।
- अफ्रीका विश्व के अन्य क्षेत्रों की तरह अभी कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली के चलते संबंधित क्षेत्र भी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। अफ्रीका में अभी तक कोरोना वायरस के 16,125 मामले सामने आए हैं और 869 लोगों की मौत हुई है।
- अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोष रोकने के निर्णय को लेकर चीन मे 'काफी चिंता' है; साथ ही उसने अमेरिका से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट के समय वह अपने दायित्वों को पूरा करे। चीन ने कहा कि अमेरिका के निर्णय से डब्ल्यूएचओ की क्षमताएं कम होंगी और महामारी के खिलाफ अभियान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कम होगा।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोके जाने पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत डब्ल्यूएचओ में सुधारों का पक्षधर तो है लेकिन ट्रंप के फैसले को गलत समय पर लिया गया फैसला मान रहा है।

डब्ल्यूएचओ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- डब्ल्यूएचओ ने भारत सहित कई देशों में टीकाकरण कार्यक्रमों को निर्देशित किया है; यह कई बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है, विश्व स्तर पर चेचक को खत्म करने और दुनिया के कई हिस्सों में पोलियो को खत्म करने जैसी उल्लेखनीय सफलताएं इसने हासिल की है।
- इसने मानसिक स्वास्थ्य पर एजेंडा तैयार करने में मदद की और अपने सदस्य को तंबाकू नियंत्रण पर ऐतिहासिक सम्मेलनों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया।
- पिछले तीन दशकों में, डब्ल्यूएचओ ने जीका वाइरस, इबोला और एचआईवी / एड्स जैसे प्रकोपों के दौरान कई राष्ट्रों की रणनीति बनाने में मदद की है।
- मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण; असंचारी रोग एवं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक; सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा प्रसार; सतत् विकास और स्वास्थ्य; पर्यावरण; स्वास्थ्य तंत्रों का विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और आपात स्थितियों में डब्ल्यूएचओ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
- इसने चेचक को खत्म करने और पोलियो को खत्म करने में मदद की है। यह यूनिसेफ, रेडक्रास सोसायटी के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में खसरे के टीकाकरण अभियान को भी चला रहा है।
- इबोला के खिलाफ एक टीका विकसित करने में एजेंसी की भूमिका वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है,जानकारों का मानना है कि कोई अन्य स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान वैज्ञानिकों, उद्योग, नियामकों और सरकारों को एक साथ नहीं ला सकता है।

आगे की राह

- विश्व स्वास्थ्य संगठन को समर्थन दिया जाना जरूरी है क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसकी भूमिका बेहद अहम है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी अन्य मानवीय सहायता संगठन के अभियानों के संसाधनों में कमी करने का भी सही समय नहीं है।
- कोविड्-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में वैश्विक एकता रहना जरूरी है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर काम कर सकें। एक वैश्वीकृत दुनिया में, वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोग जनकों को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर नहीं रोका जा सकता है ऐसी स्थिति में, डब्ल्यूएचओ अकसर आवाज बुलंद करता रहा है, कि राष्ट्रों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होना अनिवार्य है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम के आलोक में विश्व स्वास्थ्य संगठन को समर्थन दिया जाना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसकी भूमिका बेहद अहम है। चर्चा कीजिये।

4. अर्थोपाय अग्रिम : आरबीआई के तरलता प्रबंधन का उपकरण

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा की है।

अर्थोपाय अग्रिम

- भारतीय रिवर्ज बैंक, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, इसलिए आरबीआई केन्द्र सरकार एवं राज्यों की सरकारों को अस्थाई ऋण सुविधाएँ देता है, इस अस्थाई ऋण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances-WMA) कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो डब्ल्यूएमए व्यवस्था के तहत सरकारें (केन्द्र एवं राज्य) भारतीय रिजर्व बैंक से निश्चित ब्याज दरों पर कुछ समय के लिए कर्ज लेती हैं।
- अर्थोपाय अग्रिम, कॉलेटरल फ्री लोन (Collateral Free Loan) होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने हेतु सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी सरकार को जरूरत पड़ती है, उसे यह राशि उधार मिल जाती है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डब्ल्यूएमए सरकार का कोई राजस्व स्रोत नहीं है। डब्ल्यूएमए व्यवस्था के द्वारा सरकार आपातकालीन स्थितियों में ऋण प्राप्त करती है।
- भारतीय रिवर्ज बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम प्रकार का ऋण कुछ समय के लिए लेने का अधिकार है। इस ऋण को केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 90 दिनों के अन्दर वापस करना होता है।
- यदि सरकारें (केन्द्र व राज्य) डब्ल्यूएमए व्यवस्था के तहत उधार लेती हैं तो उन्हें तत्कालीन रेपो दर के बराबर ब्याज भी चुकाना होता है। यदि डब्ल्यूएमए की निर्धारित सीमा से अधिक सरकार द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता है तो ब्याज दर भी अधिक हो जाती है। बढ़ी हुई ब्याज दर तत्कालीन रेपो दर से 2 प्रतिशत अधिक होती है। वर्तमान में रेपो दर 4.4% है, अतः डब्ल्यूएमए व्यवस्था के तहत ऋण पर भी ब्याज दर 4.4% होगी।

> - **रेपो दर:** रेपो दर, वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं।

डब्ल्यूएमए की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोका जा सके, किन्तु लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे अन्य संकट के अलावा तरलता पर संकट आ सकता है; अतः आरबीआई बाजार में तरलता को सुनिश्चित करने हेतु कई उपायों के अतिरिक्त डब्ल्यूएमए व्यवस्था को भी अपनाती है।
- ध्यातव्य है कि सरकारें (केन्द्र एवं राज्य) पूरे वित्त वर्ष का बजट बनाती हैं। बजट में सरकार की प्राप्ति (Reciepts) और व्यय (Expenditure) का अनुमान लगाया जाता है, किन्तु कई अवसरों पर सरकार की प्राप्ति या आय उसके व्यय से कम हो जाती है; अतः सरकार अपने इस अस्थाई बेमेल (Temporary Mismatch) को पाटने हेतु बाजार की बजाय आरबीआई से उधार लेती है। वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों को राजस्व की प्राप्ति कम हो रही है, अतः उन्हें दैनिक खर्चों (यथा-कर्मचारियों का वेतन आदि) को निपटाने हेतु डब्ल्यूएमए की व्यवस्था के तहत ऋण की आवश्यकता है।

डब्ल्यूएमए की सीमा निर्धारण

- देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की जरूरत के मद्देनजर आरबीआई समय-समय पर डब्ल्यूएमए के तहत ऋण लेने की सीमा में बदलाव करती रहती है।
- डब्ल्यूएमए के तहत ऋण सीमा कितनी होनी चाहिए? इसके निर्धारण में आरबीआई के साथ-साथ केन्द्र सरकार की भी भूमिका होती है।
- वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण डब्ल्यूएमए की सीमा में बदलाव किया गया है। इसके पहले भी ऐसा किया जा चुका है, यथा-अस्सी के दशक में जब देश में भयंकर सूखा पड़ा था तो कई राज्यों को भारी राजकोषीय घाटा उठाना पड़ा था, इस स्थिति में आरबीआई ने दो बार राज्यों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा बढ़ायी थी।

वर्तमान में डब्ल्यूएमए की सीमा

डब्ल्यूएमए की व्यवस्था के तहत ऋण प्राप्त करने की सीमा, केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग होती है-

केन्द्र:

- भारतीय रिवर्ज बैंक ने अपनी प्रेस प्रकाशन में 20 अप्रैल, 2020 को सूचना दी कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने हेतु भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष समय के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा को भारत सरकार (अर्थात् केन्द्र सरकार) के लिए संशोधित कर दो लाख करोड़ रूपये किया जायेगा।
- हालाँकि डब्ल्यूएमए की उपर्युक्त सीमा में आगे चलकर और परिवर्तन किया जा सकता है (स्थिति के अनुसार)।

राज्य:

- भारतीय रिवर्ज बैंक ने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए समग्र रूप से डब्ल्यूएमए की सीमा को 31 मार्च, 2020 के स्तर से 60 प्रतिशत अधिक कर दिया है।
- 31 मार्च, 2020 तक राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा 32,225 करोड़ रूपये थी किन्तु अब यह 60% बढ़कर 51,560 करोड़ रूपये हो गयी है।
- अलग-अलग राज्य के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा अलग-अलग होती है। वर्तमान में सबसे अधिक डब्ल्यूएमए की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है (5,680 करोड़ रूपये। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य का स्थान आता है।

सरकारों ने बाजार से ऋण क्यों नहीं लिया

- केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें बाजार से भी ऋण लेती हैं, जिसमें आम आदमी का भी पैसा इनके पास पहुँचता है।
- वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण बिजनेस इकाईयाँ बन्द पड़ी हैं और लोगों के पास रोजगार नहीं है (बेरोजगारी की हालत में लोगों के पास बचत नहीं हो पा रही है)। इस स्थिति में सरकारों को बाजार से ऋण लेने में दिक्कत आ सकती है।
- यदि सरकार ने आम जनता से पैसा उधार ले लिया तो अर्थव्यवस्था में माँग (Demand) भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास बाजार से वस्तुएँ एवं सेवाओं को खरीदने के लिए धन नहीं बचेगा।

चुनौतियाँ

- आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार का उधार पहले से ही काफी ज्यादा है और राजस्व अपेक्षानुरूप प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे कि इस उधार को चुकाया जा सके। इस स्थिति में डब्ल्यूएमए या अन्य तरीकों से उधार लेना वित्तीय घाटा को और गंभीर बना सकता है।
- कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके कारण आर्थिक गतिविधियाँ काफी कम हुई हैं। इस स्थिति में सरकार को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से अपेक्षाकृत कम कर संग्रहण (Tax Collection) होगा, जो उधार को वापस करने में प्रमुख बाधा साबित हो सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र और राज्य सरकारों की कुल उधारी 10,49,323 करोड़ रूपये थी जबकि यह वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 13,44,521 करोड़ रूपये हो गयी, जो स्थिति की गंभीरता को प्रकट कर रही है।
- लोगों के रोजगार छिनने से प्रत्यक्ष कर संग्रहण भी कम होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक तीन प्रतिशत तक जा सकती है। इससे भारत के कई उद्योग बंद हो सकते हैं, जिससे सरकार की प्राप्ति (Reciepts) पर बुरा असर पड़ेगा, जो सरकार की देनदारियों को चुकाने में बड़ी बाधा बन सकता है।

आरबीआई के अन्य उपाय

- आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि बाजार में तरलता को सुनिश्चित करने हेतु लगभग एक लाख करोड़ रूपये विभिन्न माध्यमों से दिये जायेंगे।
- आरबीआई ने चुनिंदा क्षेत्रों (यथा-एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान आदि) के लिए लक्षित दीर्घावधि रेपो संचालन (LTRO) की सुविधा प्रदान की है ताकि ये क्षेत्र दीर्घावधि में अपने ऋण को वापस कर सकें। उल्लेखनीय है कि रेपो दर के तहत लिया गया ऋण अल्पावधि में वापस करना होता है।
- आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी (SIDBI) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की पुनर्वित्त सुविधा (Refinance Facility) को बढ़ाया है। यहाँ पुनर्वित्त सुविधा का तात्पर्य है कि नाबार्ड, सिडबी आदि को पहले आरबीआई वित्त उपलब्ध कराने की अनुमति देती है फिर ये संस्थाएँ बैंकों, एनबीएफसी आदि के माध्यम से लोगों को ऋण के रूप में वित्त उपलब्ध कराती हैं। नार्बाड कृषि क्षेत्र को, सिडबी उद्योग को और एनएचबी आवास योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराती है।
- आरबीआई ने रिवर्स रेपों दर को भी बढ़ाया है ताकि बैंक अपने धन को आरबीआई के पास जमा करने की बजाय लोगों को अधिक ऋण बाँटें।
- लोगों को अपने ऋण की ईएमआई जमा करने में भी छूट दी गयी है।

आगे की राह

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को बढ़ाना, तात्कालिक रूप से एक उचित कदम है क्योंकि इस समय सरकार को आय कम प्राप्त हो रही है।
- हालाँकि केन्द्र एवं राज्य दोनों को मिलकर एक ऐसी दीर्घकालीन रणनीति बनानी चाहिए जिसके माध्यम से न सिर्फ उधारी (Borrowings) की चुनौती से निपटा जा सके बल्कि अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति प्रदान की जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) से आप क्या समझते हैं? अर्थोपाय अग्रिम की आवश्यकता के साथ-साथ इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

5. भारत में इमरजेंसी बेसिक इनकम की व्यावहार्यता

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लगाये गये राष्ट्रव्यापी जनता कर्फ्यू की अपील सफल रही,इससे यह प्रदर्शित होता है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए लोग अपने राजनीतिक झुकाव से परे जा कर सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं।
- इसका दूसरा पक्ष यह है कि भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से लगभग 50 करोड़ कामकाजी व्यक्ति जुड़े हुए हैं और कोविड-19 से सम्बंधित लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

परिचय

- गौरतलब है कि कोरोना वायरस से अब तक वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की मृत्यु हुई है तथा करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर से गुजर रही है। कई फर्म और श्रमिक दल निष्क्रिय बने हुए हैं, उत्पादन में स्थिरता आ गयी है। इस स्थिति को नोबल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमन ने "कोरोनाकोमा" कहा है,जो एक चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा के आर्थिक समतुल्य है।
- पॉल क्रुगमन ने इस संकट में अर्थव्यस्था के पुनर्संयोजन के लिए दो घटकों को शामिल करने को कहा जिसमें पहला, तत्काल आपदा राहत घटक है जो बेकार हो चुकी फर्मों और श्रमिकों को त्वरित पैकेज प्रदान कर उनके अस्तित्व को सुनिश्चत करेगा। दूसरे घटक का उद्देश्य लॉकडाउन के निकास चरण के दौरान उत्पादन को पुन: आरंभ करना है।

भारत द्वारा किए गये प्रमुख राहत उपाय:

- भारत जैसे देश के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र और सामाजिक पहलुओं की अशक्त स्थिति के साथ, पहला घटक दूसरे के मुकाबले बहुत कठिन होगा। हालाँकि केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ राहत उपायों की घोषणा की है, परन्तु वे चुनौती को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से अपर्याप्त हैं। अधिकांश देशों की तुलना में, भारत के राहत-सह-प्रोत्साहन के उपाय जनसँख्या प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम है।
- जीडीपी में प्रतिशत के अनुरूप राहत पैकज की हिस्सेदारी कुछ इस प्रकार है :
  - **1.7 ट्रिलियन रुपये (जीडीपी का 0.08%)** : इसमें शामिल है-भोजन, गैस और निम्न आय वाले लोगों को नगद हस्तांतरण,स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस कवरेज, कम वेतन वाले श्रमिकों को वेतन समर्थन।
  - **150 बिलियन रुपये (जीडीपी का 0.1%)**: इसमें शामिल है-स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत कोविड-19 के लिए टेस्टिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स ,आइसोलेशन बेड और ICU पर अतिरिक्त खर्च।
  - **लगभग 400 बिलियन रुपये (जीडीपी का 0.2%)**: इसमें राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त राशन और नगद हस्तानांतरण शामिल है।
- इसी तरह, सभी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, एक व्यापक आम सहमति बन रही है कि कैसे इस संकट के समय में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े लाखों लोगों को राहत प्रदान की जाए जो अपने दैनिक वेतन के बिना अनिश्चित भविष्य को देख रहे हैं।

विभिन्न देशों द्वारा दिए गये राहत पैकेज

- अमेरिका ने 20 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के आधार पर 2.2 ट्रिलियन डॉलर प्रोत्साहन की घोषणा की।
- मलेशिया (जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में चार गुना है) ने भारत से 16 गुना बड़ा पैकेज की घोषणा की है।
- थाईलैंड, जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में दो गुना अधिक है ने भारत से 10 गुना बड़े पैकज की घोषणा की है।
- यहां तक कि गरीब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत की तुलना में बड़े पैकेज घोषणा की है।

अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के लोगों को सुसंगत समर्थन की आवश्यकता

- हमें नकद हस्तांतरण के माध्यम से तत्काल और अतिआवश्यक सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और उन योजनाओं को रद्द करना होगा जिन्हें अभी लागू करना मुश्किल है।
- कुछ राज्यों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन बढ़ाने की घोषणा की है ।
- इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित छोटे और मध्यम उद्योग अपने कर्मचारियों को तुरंत निकालना शुरू कर देंगे। इन उद्यमों में कर्मचारियों की व्यवस्था ज्यादातर लोगों की नजर में अदृश्य है, और इसलिए इसे प्रभावी रूप से ट्रैक करना असंभव हो जाता है। अतः ऐसे उद्यमों से अपील की जानी चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को ना निकाले। सरकार को भी इन उद्यमों की सहायता करनी चाहिए।
- सरकार के अलावा, दो अन्य प्रमुख समुदाय कॉरपोरेट्स (सीएसआर), और स्थानीय समुदाय हैं, जिन्हें इस बचाव अभियान में शामिल होना चाहिए।
- इसके साथ ही सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि कैसे सरकारी सहायता का यह हस्तानांतरण फूल-प्रूफ और लीक-प्रूफ बनाया जाए।

चुनौतियाँ

- संकट के इस समय में हमारे पास 'इमरजेंसी बेसिक इनकम' (ईबीआई) के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचता है। परंतु ईबीआई कार्यक्रम की अपनी चुनौतियां भी हैं। जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं-
- ईबीआई कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। ऑफ-बजट उधारी (जो बजट में शामिल ना हो) के मदद के बिना, केंद्र सरकार के लिए इस तरह के कार्यक्रम को फंडिंग करना संभव नहीं होगा।
- यहां तक कि अगर सरकार कुछ गैर-जरूरी खर्चों (उदाहरण के लिए स्थापना लागत), और कुछ कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के फंड में कटौती कर दे, तब भी इबीआई फंड के लिए घटनाएं पर्याप्त नहीं हो सकेगा।
- इसके अलावा इबीआई को लागू करना भी कठिन चुनौती होगी। यद्यपि अब तक लगभग सभी के पास एक विशिष्ट आईडी (आधार) है, परन्तु हर किसी के पास चालू बैंक खाता या मोबाइल या इंटरनेट (ई-ट्रांसफर के लिए) उपलब्ध नहीं है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 से इन मापदंडों के आधार पर नवीनतम जिलावार रिपोर्ट आई है जो यह प्रदर्शित करती है कि बैंक खातों और मोबाइल फोन उपलब्ध होने के बावजूद, अभी भी कई जिलों में विभिन्नतायें मौजूद थीं। अधिकांश जिलों में इंटरनेट की पहुंच भी सीमित थी।

निष्कर्ष

- केंद्र को इस कार्यक्रम के लिए फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि राज्य एक समय में वित्त की चिंता किये बिना कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसकी खामियों पर ध्यान केन्द्रित कर सके।
- विशेषज्ञ इस बात की वकालत करते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से ईबीआई प्रदान की जा सकती है, यह न केवल संभावित सामाजिक अशांति को अवरुद्ध करेगा, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सतत मांग को भी सुनिश्चित करेगा।
- कई जनप्रतिनिधियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कसौटी होगी, क्योंकि वे उन लोगों की समस्याओं का सामना करेंगे जो जमीनी स्तर पर इस स्थिति से जूझ रहे हैं।
- अन्य देशों की तरह, भारत भी लॉकडाउन की अवधि तक ईबीआई को वित्तपोषित करने के लिए कुछ अपरंपरागत विकल्प, जैसे कि एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल परपज व्हीकल), का अन्वेषण कर सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर इमरजेन्सी बेसिक इनकम प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किस प्रकार सहायक होगा? चर्चा करें।

6. स्वच्छता कार्यकर्ता : कोविड-19 के विरूद्ध पहली पंक्ति के योद्धा

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि देश में सफाई कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा किट प्रदान कर दिये गये हैं और कोरोना वायरस के संबंध में प्राधिकारी विश्व स्वास्थ संगठन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं।
- न्यायमूर्ति एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूति बी. आर. गवई की तीन सदस्यीय खंडपीठ को केन्द्र सरकार ने एक जनहित याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। विदित हो कि यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरनाम सिंह ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

परिचय

- कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। घातक कोरोना के आतंक से देशभर में लॉकडाउन जारी है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक ओर हर कोई अपने-अपने घरों में शरण लिए हुए है वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल कर आपातकालीन सेवा देने में जुटे हुए हैं।
- उन्हीं में से एक वर्ग सफाई कर्मियों का भी है, जो हर जगह गंदगी साफ करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इसके बावजूद वह लोग रोज सफाई के काम में लगे रहते हैं।
- जब लोग अपने घरों में रहते हैं, तब वे घर-घर जाकर कचरा संग्रह करने में लगे रहते हैं। यह सफाई कर्मी एक दो जगह नहीं बल्कि हर जगह अपने जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहते हैं। इन सफाई कर्मियों को हम उनका कर्तव्य समझकर छोड़ दें तो यह उन सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान नहीं होगा।
- समाज के सभी वर्गों का कर्तव्य बनता है कि इन सफाई कर्मियों के जज्बे को सलाम करते हुए उनका स्वागत करें। असल में देखा जाए तो कोरोना के जंग में यह लोग भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

सफाई कर्मियों के समक्ष चुनौतियाँ

- इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा उन लोगों की सराहना हो रही है जो खुद की जान की परवाह किए बिना कोरोना के इस संकटकाल में अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले और सफाई कर्मी। ये वो करोना वॉरियर्स है जिनके बिना ये देश कोरोना के खिलाफ अपनी जंग नहीं जीत सकता, लेकिन देश के कई हिस्सों में सफाई कर्मचारी बिना सेफ्टी गेयर्स के काम करने को मजबूर हैं।
- इन्हें मास्क, ग्लव्स, गमबूट (Gumboot), सैनिटाइजर, हेलमेट, चश्मा कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो सफाई कर्मचारियों की जान से सीधा खिलवाड़ को दर्शाता है।
- सफाईकर्मी सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों, सीवरों, सेप्टिक टैंकों, सामुदायिक भवनों और सार्वजनिक शौचालयों को साफ और स्वच्छ रखने के कार्य में जुटे रहने के साथ वायरस के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किन्तु बिना सुरक्षा उपकरणों के अगर इनमें से कोई भी संक्रमित हुआ तो कोरोना वायरस को कम्युनिटी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी।
- पाँच मिलियन सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मी तथा सफाईकर्मी जो कोविड-19 महामारी के दौरान भी काम करना जारी रखे हुए हैं वे असुरक्षित, तो है ही साथ ही लोग उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
- सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि उन्हें प्रभावित घरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही उन लोगों के बारे में जो उच्च जोखिम में हैं।

- यदि सफाई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनको अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से महिला स्वच्छता कार्यकर्ता, जो शहरी स्वच्छता कर्मचारियों के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण करती हैं।
- सफाई कर्मियों की महत्ता के बावजूद भी

सरकार और आम लोगों द्वारा इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के अभाव में सफाई कर्मियों के मध्य कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूकता का भी अभाव देखा जा रहा है।

सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए

- **सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करें :** अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में फ्रंटलाइन स्टाफ को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की सख्त कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि उन्हें मास्क, रबर के दस्ताने, एप्रोन, सुरक्षात्मक जूते या, सैनिटाइटर, और साबुन अतिशीघ्र मुहैया कराये।
- महाराष्ट्र में, सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग स्वच्छता कर्मचारियों के लिए पीपीई खरीदने के लिए किया है, और स्वच्छता कर्मचारियों को पाली (shift) में काम करने की अनुमति दी है। तेलंगाना में, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए मास्क का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे अन्य राज्यों को भी अपनाने की आवश्यकता है ।
- **आर्थिक सहायता प्रदान करें :** यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर किया जा सकता है।
- **वेतन की सुरक्षा :** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक सलाह जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन की रक्षा की जानी चाहिए, अगर वे लॉकडाउन के कारण ड्यूटी करने में असमर्थ हैं।
- **स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ काम करने वाले संगठनों को सीएसआर फंड का आवंटन:** कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि सीएसआर फंड का उपयोग कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
- **स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान करें:** निवासी कल्याण संघों (RWA) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छता कार्यकर्ता जो अपने इलाकों में काम करते हैं, उनके पास उचित पीपीई हो। यदि आवश्यक हो, तो सफाईकर्मी को उचित सुरक्षा गियर सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर धन एकत्र किया जा सकता है।
- आरडब्ल्यूए इस बात का भी समर्थन कर सकते हैं कि सभी स्वच्छता कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान की जा रही है की नहीं।
- सांसदों, विधायकों और नगरपालिका पार्षदों के पास अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **भोजन और बोर्डिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करें :** चेन्नई में, सफाई कर्मचारियों को अम्मा कैंटीन में मुफ्त भोजन दिया जाता है। स्थानीय समुदाय यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन जुटा सकते हैं कि स्वच्छता कर्मचारियों की भोजन और अन्य आपूर्ति तक पहुँच हो। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अपने परिवार के लिए भोजन प्रदान करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वे अपनी नौकरी पर हैं।
- अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें क्वारंटाइन करने के संदर्भ में, राज्य सरकारों को नामित छात्रावासों और आवासीय सुविधाओं युक्त बोर्डिंग उपलब्ध कराने के विकल्प का पता लगाना चाहिए।
- दिल्ली सरकार ने एक ऐसा ही कदम उठाया है, जिसमें डॉक्टरों के लिए होटल के कमरे किराए पर लिए गए हैं जो कोविड-19 के साथ अपने परिवारों को संक्रमित करने के डर से घर नहीं जाना चाहते हैं।
- **स्वच्छता कर्मचारियों को हौसला बढ़ाना:** जिस तरह से देश के स्वास्थ्य कार्यकर्ता जीवन बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारे सफाई कर्मचारी भी हर वार्ड और मोहल्ले में काम कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित और स्वस्थ रहें। यह हम सभी के लिए इसे पहचानने का समय है। अतः हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा सफाई कर्मियों का समूह भी मौजूदा समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी संकट से अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा है। इसलिए स्थानीय सरकार को इनको हर संभव सुरक्षा व सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा आम जनता को भी इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के साथ हर संभव मदद करने की कोशिश करना चाहिए।
- नगरपालिका को विशेष रूप से ध्यान दिये जाने कि आवश्यकता है कि कोविड -19 से संक्रमित कचरा सड़कों के किनारे रहने वालों, बच्चों या गरीबों को संक्रमित न कर पाये। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि यह कचरा आम डंपिंग ग्राउंड तक न पहुंचे।
- कोरोनो वायरस प्रत्यक्ष स्पर्श और दूषित सतहों और वस्तुओं के माध्यम से भी प्रसारित होता है। प्राय: देखा गया है कि भारत में कचरा पृथक्करण के बुनियादी नियमों का पालन अभी भी पूरी तरह से नहीं किया जाता है। ऐसे में घरों एवं अस्पतालों द्वारा उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के पृथक निपटान की आवश्यकता के बारे में और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोरोना वायरस महामारी से सफाई कर्मियों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करें।

7. कोविड-19 महामारी बनाम सतत् विकास लक्ष्य (SDG)

परिचय

- कोविड-19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार, सप्लाई चैन का व्यवधान, वस्तुओं और लॉजिस्टिक्स सहित अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के उम्मीद है। इस महामारी के द्वारा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक माध्यमों से वैश्विक विकास के उद्देश्यों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ने के आसार है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के 'सतत् विकास लक्ष्य (SDG) पर पड़ने वाले प्रभाव को अधिक प्रमुखता से देखा जा रहा है।

सतत् विकास लक्ष्य-(Sustainable Development Goals)

- 'सतत् विकास लक्ष्य', जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 193 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- 'सतत् विकास लक्ष्य', सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित है जिसका मूल मंत्र है 'कोई पीछे न छूटे'। इसका मुख्य उद्देश्य "विकास के सभी आयाम, सभी जगह, सभी के लिए समावेशी होनी चाहिए और उसका निर्माण हर किसी की, विशेषकर सबसे लाचार और हाशिए पर जीवन व्यतीत करने वालों की भागीदारी से होना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों की ऐतिहासिक योजना 1 जनवरी 2016 को शुरू की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है
- सतत् विकास लक्ष्य के एजेंडें में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी शामिल हैं।
- सतत् विकास लक्ष्य के माध्यम से माना गया है कि अब केवल आर्थिक वृद्धि पर फोकस करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और अधिक समतामूलक समाजों तथा अधिक संरक्षित एवं अधिक संपन्न पृथ्वी पर फोकस करना होगा। इसमें सबसे अधिक मान्यता इस बात की है कि वैश्विक और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए केवल वैश्विक और परस्पर जुड़े समाधानों की ही आवश्यकता है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए सरकारों, कारोबार जगत, प्रबुद्ध समाज और व्यक्तियों के बीच नए सिरे से वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है। हम जैसे-जैसे 169 उद्देश्यों की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे वैसे-वैसे राष्ट्रीय और वैश्विक विकास को अधिक सतत् और अधिक सुदृढ़ मार्ग पर मोड़ते जाएंगे।

भारत में सतत् विकास लक्ष्य

- नीति आयोग सतत् विकास लक्ष्यों और उनके उद्देश्य से जुड़ी योजनाओं की पहचान और इन योजनाओं को अग्रणी एवं सहायक मंत्रालय तक पहुँचाने एवं दिशा निर्देश देने का कार्य करती है।
- सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (SDG India Index) को केन्द्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टिट्यूट तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साथ मिलकर तैयार किया जाता है। 2019 में भारत को 100 अंकों में से 60 अंक प्राप्त हुए थे जो कि 2018 के 57 अंक की तुलना में बेहतर था।
- सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की कुंजी राज्य सरकारों के हाथ में है क्योंकि राज्य ही जनहित को प्राथमिकता देने और लागू करवाने में ज्यादा समर्थ है।
- सरकार के अनेक प्रमुख कार्यक्रम जैसे-स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया और डिजिटल इण्डिया, सतत् विकास लक्ष्यों के मूल है। राज्य और स्थानीय सरकारें इनमें से अनेक कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाती है।
- हाल ही में आयी कोरोना महामारी से शायद ही कोई क्षेत्र अछूता हो और आने वाले समय में सभी समस्याओं के बढ़ने के आसार है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार दुनिया की दो-तिहाई आबादी कोरोना वायरस से प्रभावित होगी, ऐसे में सतत् विकास लक्ष्य को 2030 तक साकार होने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया वैश्वीकरण के दौर में हैं तथा समस्त देशों का एक दूसरे बीच जुड़ाव है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास बंद होने से भी अर्थव्यवस्था की स्थिति जटिल हो गयी है।

कोविड-19 और सतत् विकास लक्ष्य

- कोविड-19 महामारी, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न ही नहीं करता बल्कि उद्देश्यों को प्राप्त करने की समयावधि पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। कोरोना महामारी के संदर्भ में विभिन्न संस्थानों के आगे की भूमिका और क्षमता, सभी राष्ट्रों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है।
- भारत जैसे विकासशील देशों में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित व्यापार में संलग्न है, विशेषकर सेवा क्षेत्र में असंगठित समूहों की कार्यप्रणाली व अक्षमता अधिक गरीबी, भुखमरी और असमानताओं को जन्म देगी जो सतत्-विकास लक्ष्य 1- शून्य गरीबी, लक्ष्य 2- शून्य भुखमरी और लक्ष्य 3-अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर की उपलब्धियों में बाधा उत्पन्न करेगी।
- सतत् विकास लक्ष्य 4-(गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) भी कोरोना महामारी से प्रभावित होगा। यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में कुल नामांकित शिक्षार्थियों में से लगभग 1.25 बिलियन शिक्षार्थी (72.9 प्रतिशत) 20 मार्च तक कोरोना वायरस प्रकोप से प्रभावित हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा दूरस्थ शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी का समर्थन किया जा रहा हैं।
- सभी बुनियादी समस्याएं एक दुसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी

फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन (UN Women) ने कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए एक चेकलिस्ट जारी की है जिसमें 10 प्रश्न पर देशो की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, (लक्ष्य -5 लैंगिक समानता)।

- लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा में वृद्धि का मामला भी देखने को आया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति हो रही असमानता में भी वृद्धि हुई है। जो कि SDG के लक्ष्य 5 से संबंधित है।
- संक्रमण को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है हाथों को धोना या साफ करना। स्वच्छ जल का सीधा संबंध स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं स्वच्छता से हैं। यू एन की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 3 billion लोगों के पास घरों में स्वच्छ जल की पहुँच नहीं हैं। कोरोना महामारी से यह समस्या और भी गंभीर होगी, जो कि SDG 6 से सबंधित है।
- कोरोना वायरस की महामारी से सतत् विकास लक्ष्य-8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि) और लक्ष्य-9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं) सबसे अधिक चिंताजनक है। सतत् विकास लक्ष्य-8 को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं मानव पूंजी जिसकी इस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर कमी होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, आर्थिक और श्रम संकट के कारण लगभग 25 मिलियन लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं।
- वही सतत् विकास लक्ष्य-9 के लिए उम्मीद की जा सकती हैं कि अब संस्थानों के नए रूप सामने आएंगे और विकास कि चाल बदल जाएगी।
- यू एन महासचिव ने दुनिया के सभी कोनों में महामारी से निपटने के लिए शांति एवं एकजुट अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के लिए अपील की जो एसडीजी के लक्ष्य-16 (विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना) के लिए उठाया गया कदम था।
- वही दूसरी ओर कम आर्थिक गतिविधियाँ पर्यावरण के लिए बेहतर हैं जो कि सतत विकास लक्ष्य-13 जलवायु कार्रवाई, लक्ष्य-14 जलीय जीवों की सुरक्षा, लक्ष्य-15 थलीय जीवों की सुरक्षा की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएंगें।
- इस समय सतत् विकास लक्ष्य-17 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जिसमें सभी लक्ष्यों को एक वास्तविकता बनाने के लिए सभी की भागीदारी की आवश्यकता होगी, जिसमें सरकारें, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन और दुनिया भर के लोग शामिल हैं। अतः कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लक्ष्य-17 सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आगे की राह

- कोरोनो वायरस महामारी मानव परिवार को एकजुटता में काम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस संकट को एक प्रेरणा में बदलने का अवसर प्रस्तुत कर सकती है। कोरोना महामारी समस्त वैश्विक जगत के समक्ष एक संकट है। ऐसे में 2015 में अनुमोदित 2030 एजेण्डा और उसके 17 सतत् विकास लक्ष्य इन चुनौतियों और इनके अन्तर्सम्बन्धों के समाधान के लिए संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण फ्रेंमवर्क प्रदान करने की आवश्यकता है।
- निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों के बदलते स्वरूप सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकते है।
- इसके अर्न्तगत सदस्य राष्ट्रों को सतत् विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का समाधान संतुलित ढंग से करना होगा।
- दुनिया पहले से ही डिजिटल कनेक्टिविटी पर भारी निर्भरता देख रही हैं। डिजिटल स्पेस ज्यादातर सेवाओं को प्रेरित कर सकती है।
- समस्त राष्ट्रों को समावेशन और एकीकरण तथा किसी को पीछे छूटने न देने के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना एक मुश्किल भरा कार्य होगा? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

1. पोस्ट–इन्टेसिव केयर सिंड्रोम

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी डबल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 से संक्रमित 6.1 प्रतिशत लोग श्वसन की समस्या, अंग की विफलता या मानसिक आघात से ग्रसित होते हैं। ऐसे रोगियों को रिकवरी के लिए एक लम्बे समय तक चिकित्सा की आवश्यकता होती हैं।
- ज्ञातव्य है कि आजकल कोविड-19 के कारण बहुत लोगों को ICU में भर्ती करना पड़ा है। ऐसा देखा जा रहा है कि ICU से निकलने के बाद कई रोगी एक विशेष सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। इसे ही पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम (Post Intensive Care Syndrom-PICS) नाम दिया गया है।
- इस सिंड्रोम में ICU से निकलने के बाद रोगी में शारीरिक, वैचारिक और मानसिक गिरावट देखने को मिलती है।

2. पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम (PICS) के लक्षण

- PICS के सर्वाधिक सामान्य लक्षण हैं-दुर्बलता, थकान, चलने-फिरने में कष्ट, अवसाद में रहना, यौन अक्षमता, अनिद्रा आदि।
- ये लक्षण कुछ महीने अथवा कई वर्षों तक रह जाते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के रोजमर्रा जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे-चलना, खाना-पीना, उसके हाव-भाव इत्यादि।

3. पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम (PICS) के कारण

- यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कृत्रिम स्वॉस प्रणाली (वेन्टिलेटर) के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस (फेफड़ों में संक्रमण) हो जाता है और साथ ही कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं।
- कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाले 33% रोगियों की मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं। इस परिस्थिति को ICU से उत्पन्न मांसपेशी दुर्बलता (ICU-Acquired Weakness-ICUAW) कहा जाता है।
- ICU से निकलने वाले रोगियों में 30-80 प्रतिशत अवसाद एवं मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित समस्याएं विकसित हो जाती हैं।

4. पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम से बचाव

- पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम (PICS) से ग्रसित मरीज को नींद न आने पर, नींद की दवा कम से कम देना चाहिए और उन्हें शीघ्रता-शीघ्र चलने-फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- PICS से ग्रसित रोगी को बढ़-चढ़ के शरीरिक (व्यायाम, योगा, दौड़) और व्यवसायिक उपचार (अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर) उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे जोड़ों एवं मांसपेशियों को सक्रिय बनाया जा सके।
- पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम (PICS) के मरीज दुर्बलता एवं थकान के कारण शिथिल पड़ जाते हैं। शरीरिक पीड़ा को महसूस करते है। ऐसे में उन्हें दर्द निवारक का सेवन कम से कम करना चाहिए एवं शारीरिक व्यायाम एवं मेडिटेसन द्वारा इस पीड़ा को दूर करना चाहिए, ताकि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके।
- ठीक हो जाने के बाद रोगी को फेफड़े और हृदय को मजबूत करने के लिए उपचार दिया जाना चाहिए। साथ ही अवसाद, चिंता आदि मानसिक रोगों का उपचार चलते रहना चाहिए।

2. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस (आईसीएन) और 'नर्सिंग नाउ' अभियान के साथ "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है ।

2. पृष्ठभूमि

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, पहली बार स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 का शुभारंभ किया गया।
- यह रिपोर्ट नर्सिंग कार्यबल की वैश्विक तस्वीर प्रदान करती है और सभी के स्वास्थ्य सुधार के लिए इस कार्यबल के योगदान का समर्थन करती है।
- यह रिपोर्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए डेटा संग्रह (डाटा कलेक्शन), नीति संवाद (पॉलिसी डॉयलाग), अनुसंधान (रिसर्च) और पक्ष में समर्थन (एडवोकेसी), और स्वास्थ्य कार्यबलों में निवेश के लिए एजेंडा तैयार करती है।

3. रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक, दुनिया भर में 5.7 मिलियन से अधिक नर्सों की कमी होगी।
- वैश्विक स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्र में प्रति 10,000 लोगों पर लगभग 36.9 नर्स हैं।
- अफ्रीकी क्षेत्र की तुलना में अमेरिका में लगभग 10 गुना अधिक नर्स हैं। अमेरिका में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 83.4 नर्स हैं, वहीं अफ्रीका में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 8.7 नर्स हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में नर्सों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गयी है, वहीं अमेरिका और यूरोप अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि वहाँ उम्रदराज नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है।
- इसके अलावा, यूरोप के कई उच्च आय वाले देश, पूर्वी भूमध्यसागरीय व अमेरिकी क्षेत्र विशेष रूप से "प्रवासी नर्सों" पर निर्भर हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया की इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए नर्स और चिकित्साकर्मी इसकी अग्रिम रेखा पर तैनात है फिर भी इन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) (जैसे- फेस मास्क, आंख-सुरक्षात्मक गियर (आई प्रोटेक्टिव गियर) और दस्ताने (ग्लव्स))की कमी, तथा कुछ मेडिकल स्टाफ को तो मानसिक तनाव जैसे मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है।

4. भारत में नर्सिंग की स्थिति

- 2018 तक, भारत में 1.56 मिलियन नर्स और 772, 575 नर्सिंग सहयोगी थे। इसमें से 67 प्रतिशत पेशेवर नर्सों की हिस्सेदारी है।
- भारत में, नर्सों की संख्या चिकित्सा स्टाफ की 47 प्रतिशत है।
- इसके साथ ही, भारत में 88% महिलाएं नर्स हैं। यह वैश्विक स्तर पर देखी गई नर्सिंग की संरचना के अनुरूप है, जहां 90 प्रतिशत महिलाएं नर्स हैं।

5. विश्व स्वास्थ्य दिवस

- विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 से हर साल 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मनाया जाता है।
- इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, दाइयों और हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया जो बहादुरी और साहस के साथ कोविड-19 से लड़ रहे हैं।
- इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की टैगलाइन है: नर्सों और दाइयों (मिडवाइव्स) का समर्थन।

6. आगे की राह

- रिपोर्ट में कहा गया है कि नर्सेस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (यूनिवर्सल हेल्थ केयर), मानसिक स्वास्थ्य (मेंटल हेल्थ), गैर-रोगजनक बीमारियों (नॉनकम्युनिकेबल डिजीज), आपातकालीन तैयारियों (इमरजेंसी प्रिपेयरनेस) और अन्य उद्देश्यों से संबंधित राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं।
- नर्स एक रोगी की गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करती हैं इसके साथ ही, संक्रमण को रोकने और नियंत्रित करने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हैं।
- सरकारों को नर्सिंग शिक्षा, नौकरियों और उनके नेतृत्व में निवेश करना चाहिए। साथ ही उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार स्थितियों के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए।

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के अंतर्गत देश की विभिन्न जेलों से लगभग 11,077 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority - NALSA) के अनुसार, कोविड-19 के कारण देश की विभिन्न जेलों में भीड़ को कम करने के मिशन के तहत यह कदम उठाया।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA)

- भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था।
- राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संविधान के अनुच्छेद '39-क', समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता एवं अवसर की समानता के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहयोग प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1), विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को बाध्य करता है।

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का कार्य

- नालसा का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और उचित विधिक सेवायें प्रदान करना है।
- नालसा, सम्पूर्ण भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएँ लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा-निर्देश निर्गत करता है।
- नालसा के द्वारा सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान किया जाता हैं। इसके अंतर्गत महिलाएं और बच्चें, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, विकलांग व्यक्ति, बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार, हिरासत में रखे गए लोग शामिल हैं।

4. नालसा का उपविभाग

NALSA को मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुका कानूनी सहायता समितियों आदि का उत्तरदायित्व सौंपा गया है

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

- भारत के हर एक राज्य में NALSA की नीतियों और निर्देशों को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए और समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान कराने के लिए तथा राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता सम्बंधित कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

- हर जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर एक जिले के जिला न्यायालय के परिसर में स्थित है और इसकी अध्यक्षता से सम्बंधित कार्य जिले के जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है।

तालुका विधिक सेवा समिति

- तालुका या मंडल के लिए तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन किया जाता है।
- हर एक तालुका विधिक सेवा समिति का संचालन एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं, जो कि इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और जो समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत होते हैं।

4. कोरोना बॉन्ड

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में इटालियन प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन द्वारा कोरोना बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा था।
- इसके लिए यूरोजोन के वित्तमंत्रियों ने 540 बिलियन यूरो के आपातकालीन बचाव पैकेज पर विचार-विमर्श किया, हालाँकि इस विचार को यूरोपीय संघ के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है।

2. कोरोना बॉन्ड क्या है

- कोरोना बॉन्ड कोरोना वायरस संकट के बीच यूरोजोन के वित्तीय संघर्ष को कम करने का एक संभावित प्रस्ताव है।
- कोरोना बॉन्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण होगा, जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस द्वारा पीड़ित यूरोजोन देशों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
- यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए ऋण की आपूर्ति यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा की जाएगी।

3. कोरोना बॉन्ड की आवश्यकता

- कोरोना बॉन्ड का लाभ यह है कि ये यूरोपीय देशों को आवश्यक वित्तीय सहायता देगा।
- राज्य अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- इन फंडों के माध्यम से, राज्य सरकारी खर्च बढ़ा कर, कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं।
- अगर यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र एकता का प्रदर्शन करने में सक्षम हुए, तो इससे यूरोप के बीच विश्वास मजबूत होगा और उन्हें कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक संकट से भी उभरने में भी मदद मिलेगी।

4. विवाद क्यों है ?

- यूरोपीय संघ के नौ देश कोरोना बॉन्ड को जारी करने का आह्वाहन कर रहे हैं जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस और स्लोवेनिया शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ (ईयू) के सभी देश इस विचार के पक्ष में नहीं हैं। इनमे जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल हैं जिन्हें यूरोपीय संघ के राज्यों में "फ्रूगल फोर" के रूप में जाना जाता है।
- इन देशों की राय है कि वित्त एक व्यक्तिगत राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इनके अनुसार ईयू के प्रत्येक देश को अपने वित्त का प्रबंधन स्वयं करना चाहिए।
- दशकों तक जर्मनी ने "श्वार्ज नल"(ब्लैक जीरो) डेट ब्रेक पॉलिसी लागू की जिसके अनुसार किसी भी परिस्थिति में सरकार को जनता से ऊधार लेने की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि फरवरी में जर्मनी ने यह घोषणा की थी कि वह इस नियम को स्थगित कर देगा।
- मार्च में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अगले नौ महीनों तक अपने परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम (एसेट परचेज प्रोग्राम) का विस्तार 750 बिलियन यूरो करने का फैसला किया। लेकिन समस्या यह थी कि आर्थिक मंदी के दौरान उत्तर में अमीर सदस्यों और दक्षिण में गरीब राज्यों के बीच बोझ का बंटवारा किस आधार पर होगा। यही समस्या कोरोना बॉन्ड में भी आई है।

5. चुनौतियाँ

- कोरोना बॉन्ड का एक नुकसान यह है कि यह आवश्यक रूप से ऋण स्थिरता में वृद्धि नहीं करेगा।
- यह अवधारणा केवल भविष्य की कर्ज माफी में मदद करेगी।
- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामान्य बॉन्ड के कार्यान्वयन में भी बहुत समय लग जाता है और इस प्रकार की देरी उन देशों के लिए सही नहीं है, जिन्हें तुरंत धनराशि की आवश्यकता है।

5. कोविड-19 महामारी और कलर कोडिंग

1. चर्चा का कारण

- केन्द्र सरकार नई क्लस्टर विकास योजना के तहत देश को पूर्ण लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन में ले जाने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके तहत देश को तीन अलग-अलग क्षेत्रों यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन में वर्गीकृत करके संकट के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

2. स्मार्ट लॉकडाउन

- केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण घटती अर्थव्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित कर, मध्यम-मार्ग (middle path) के दृष्टिकोण को अपनाया है।
- सरकार ने लॉकडाउन एक्सटेंशन (3 मई) के दौरान 20 अप्रैल से स्मार्ट लॉकडाउन अपनाने का फैसला किया है।
- स्मार्ट लॉकडाउन सरकार को लॉकडाउन का विस्तार करने की अनुमति देगा जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
- यह कुछ क्षेत्रों में उत्तरजीविका सुनिश्चित करने के लिए, छूट देने की अनुमति देता है।

3. देश का क्षेत्र-वार वर्गीकरण

- लॉकडाउन 2.0 या स्मार्ट लॉकडाउन के तहत, देश को तीन प्रमुख क्षेत्रों- लाल, नारंगी और हरे रंग में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है।
- ट्रैफिक लाइट से व्युत्पन्न ये रंग सरकार द्वारा घोषित क्लस्टर विकास योजना (CDP) का समर्थन करेंगे एवं अर्थव्यवस्था को गति देंगे।

4. कलर कोडिंग द्वारा क्षेत्रों का वर्गीकरण

रेड जोन:

- इस जोन मे ,किसी भी गतिविधि की अनुमति के ऊपर गंभीर प्रतिबंध होंगे।
- भारत में कोरोना से संबंधित 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में योगदान देने वाले जिलों को रेड जोन घोषित किया गया हैं। अर्थात् 170 हॉट स्पॉट जिले घोषित किए गये हैं।
- रेड जोन में 15 से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिले शामिल होंगे। (प्रत्येक सोमवार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गणना की जाएगी)

ऑरेंज जोन:

- ऑरेंज जोन के अंतर्गत सीमित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाएगा।
- इस जोन में आवश्यक सेवाओं के कर्मियों के लिए और चालू सीजन के लिए खेती तथा फसल गतिविधि की अनुमति होगी।
- इलाके में 14 दिनों से कोई ताजा मामला सामने नहीं आना चाहिए।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑरेंज जोन को रेड जोन के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है।

ग्रीन जोन:

- इस क्षेत्र में देश में सामान्य स्थिति की भावना लाने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में अधिकतम ढील दी जाएगी।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक दूरी के उचित रख-रखाव के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) खुलेंगे।
- इसी तर्ज पर मनरेगा और अन्य प्रोजेक्ट भी होंगे।
- ग्रीन क्षेत्र में 28 दिनों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आने चाहिए वरना ऑरेंज जोन में रूपांतरित हो सकता है।

6. निहंग सिख

1. चर्चा का कारण

- हाल ही मे पंजाब के पटियाला में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और ASI हरजीत सिंह का हाथ काट दिया। हमला करने वाले लोग 'निहंग सिखों' की पारंपरिक वेशभूषा में थे।

2. परिचय

- रत्नाकर महान कोश के अनुसार निहंग शब्द के कई मतलब हैं- जैसे तलवार, कलम, घोड़ा, मगरमच्छ। पारिभाषिक रूप में जो बिना किसी शंका के हो वह निहंग है जिसका किसी से मोह न हो, निहंग है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब और श्री दशम ग्रन्थ साहिब में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। श्री दशम ग्रन्थ साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के उपदेश हैं।
- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के अनुसार, निहंग शब्द फारसी से आया है, जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। ये नाम मुगलों ने सिख लड़ाकों को दिया था, क्योंकि जिस तरह पानी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना बेहद मुश्किल था।

3. कौन है निहंग सिख

- सिख धर्म के ग्रंथों में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने वर्ष 1699 में श्री केशगढ़ साहिब में खालसा पंथ बनाया था और उस समय उन्होंने अपने पांच चहेतों को अपना बाणा और बाणी दी थी। ऐसा माना जाता है कि वही पांचों, निहंग सिख हैं। इसी परंपरा के सिखों ने ही अभी तक उन बाणा और बाणी को संभाल के रखा है। इन्हें गुरु की लाड़ली फौज भी कहा जाता है।

4. होला मोहल्ला के अवसर पर दिखाते हैं युद्ध कौशल

- अपने मार्शल युद्ध कौशल की वजह से धार्मिक तौर पर इन्हें योद्धा का दर्जा मिला हुआ है, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी गुरुद्वारों की रक्षा करना और युद्ध के समय सबसे आगे रहना है। आज की तारीख में निहंग मुख्य तौर पर होला मोहल्ला जैसे त्योहारों पर अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। ये परंपरा गुरु गोबिंद सिंह जी के जमाने से ही चली आ रही है।

5. अन्य तथ्य

- निहंगों के बारे में कहा जाता है कि उनका अपना एक डेरा और जीवन जाने का एक विशिष्ट तरीका होता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें डेरे की देखभाल की जिम्मेदारी होती है जबकि अन्य लोग राज्यों में घूमते हैं।
- कहा जाता है कि डेरे में निहंग सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यही नहीं ये वर्षभर के लिए अपने कार्यक्रमों का एक कैलेन्डर जारी करते हैं।
- निहंग सिखों को ऐतिहासिक रूप से दो दलों में विभाजित किया गया है। एक-तरण दल तथा दूसरा-बुद्ध दल। बुद्ध दल का मुख्यालय तलवंडी साहब में हैं, जबकि तरण दल का मुख्यालय होशियारपुर में है।
- ये अपने डेरे को संचालित करने के लिए गाँवों से चंदा इकठ्ठा करते हैं तथा इसके अलावा ये कृषि कार्य भी करते हैं।

7. कोविड–19 की वजह से टीकाकरण में देरी

1. चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दुनियाभर में 11.7 करोड़ बच्चे खसरा के खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि कई देशों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच टीकाकरण अभियान को सीमित कर दिया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण 24 देशों ने टीकाकरण के अभियान को रोक दिया है। कोरोना वायरस के कारण 13 अन्य देशों में भी टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ है ।
- यूनिसेफ के मीजल्स और रूबेला अभियान (M & RI) की ओर से कहा गया है कि 37 देशों में 117 मिलियन यानी 11.7 करोड़ से अधिक बच्चे इसके कारण प्रभावित हो सकते हैं।

2. कोविड-19 महामारी का खसरा टीका पर प्रभाव

- कोरोना महामारी के कारण विश्व के कई देशो में लॉकडाउन हैं, इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बाधित हो रहा है।
- कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव के कारण टीका अभियान मे रुकावट पैदा हो रहा है।
- यू एन समूह ने एक बयान जारी कर कहा, कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए, टीकाकरण अभियान को फिलहाल बंद किया गया है।
- स्वास्थ्य संगठनों से आग्रह किया गया है कि ऐसे बच्चों को ट्रैक किया जाए जिनको मीजल्स का टीका नहीं लगा है।

3. खसरा-रूबेला अभियान (Measles & Rubella Initiative –M&RI)

- खसरा और रूबेला अभियान की शुरुवात वर्ष 2001 में की गई थी। वर्ष 2000 की तुलना मे 2010 में 90% खसरा संक्रमण मे कमी देखी गयी थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है।
- यह नौ माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से अस्पतालों एवं स्कूलों के माध्यम से लगाया जाता है।
- दुनिया भर में यह उल्टी-दस्त, खांसी, बुखार, निमोनिया और दिमागी बीमारियों से होने वाले मृत्यु-दर को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

4. खसरा (Measles)

- खसरा एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के नाक और गले में पाया जाता है और खांसी और छींक के जरिए हवा में फैल जाता है।
- खसरा के लक्षणों में बुखार, खांसी और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ते हैं। शरीर पर चकत्ता निकलते ही बुखार 104°F (40°C) या इससे अधिक बढ़ जाता है।
- खसरा, मीजल्स विषाणु (measles virus) के द्वारा होता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के रिपोर्ट के अनुसार खसरा से हर साल करीब दो करोड़ बच्चे प्रभावित होते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चों की उम्र पांच साल से कम होती है। वर्ष 2018 में खसरा की वजह से 140,000 बच्चों की मौत हुई थी ।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंड्रोम

प्र. पोस्ट-इंटेसिव केयर सिंड्रोम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पोस्ट इंटेसिव केयर सिंड्रोम (PICS) के मरीज दुर्बलता एवं थकान के कारण शिथिल पड़ जाते हैं।
2. यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक बेंटिलेटर के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिम हो जाता है और कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और 2 ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः पोस्ट इंटेसिव केयर सिंड्रोम (PICS) के मरीज दुर्बलता एवं थकान के कारण शिथिल पड़ जाते हैं एवं शारीरिक पीड़ा को महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कृत्रिम स्वॉस प्रणाली (वेन्टिलेटर) के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिम (फेफड़ों में संक्रमण) हो जाता है और साथ ही कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। इस तरह कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अतः उत्तर (c) होगा। ■

2. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पहली बार स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 का शुभारंभ किया गया।
2. भारत में नर्सों की संख्या कुल चिकित्सा स्टाफ की 87 प्रतिशत है।
3. इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की टैगलाइन है "नर्सों और दाइयों का समर्थन"।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, पहली बार स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 का शुभारंभ किया गया। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की टैगलाइन है- "नर्सों और दाइयों का समर्थन"। इसलिए कथन 1 और 3 सत्य हैं। भारत में नर्सों की संख्या कुल चिकित्सा स्टॉफ की 47 प्रतिशत है (ना कि 87 प्रतिशत)। इस तरह कथन 2 गलत है। अतः उत्तर (c) होगा। ■

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

प्र. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NAISA) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कोविड-19 के कारण हाल ही में देश की विभिन्न जेलों में भीड़ को कम करने के लिए 11,077 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है।
2. भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1887 के तहत किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और 2 ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के अंतर्गत देश की विभिन्न जेलों से लगभग 11,077 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। (ना कि 1887)। इसलिए कथन 2 असत्य है। जबकि कथन 1 सत्य है। अतः उत्तर (a) होगा। ■

4. कोरोना बॉन्ड

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कोरोना बॉन्ड कोरोना वायरस संकट के बीच यूरोजोन के वित्तीय संघर्ष को कम करने का एक संभावित प्रस्ताव है।
2. राज्य सरकारों का कहना है कि राज्य अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और 2 ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः कोरोना बॉन्ड कोरोना वायरस संकट के बीच यूरोजोन के वित्तीय संघर्ष को कम करने का संभावित प्रस्ताव है। राज्य अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कथन 2 असत्य है। जबकि कथन 1 सत्य है। अतः उत्तर (a) होगा।

5. कोविड-19 महामारी और कलर कोडिंग

प्र. कलर कोडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कलर कोडिंग के अंतर्गत देश को चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है।
2. भारत में 80% से अधिक कोविड-19 के मामलों वाले जिले को रेड जोन घोषित किया गया है।
3. यदि किसी जिले में 14 दिनों से कोविड-19 के कोई ताजा मामला सामने नहीं आता है तो उसे ऑरेंज जोन में रखा जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कलर कोडिंग के अंतर्गत देश को तीन (न कि चार) प्रमुख क्षेत्रों (यथा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में विभाजित किया है। भारत में 80% से अधिक कोविड-19 के मामले वाले जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं यदि किसी जिले में 14 दिनों से इसका कोई मामला सामने नहीं आता है तो उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

6. निहंग सिख

प्र. निहंग सिख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. निहंग शब्द फारसी से बना है, जिसका अर्थ होता है मगरमच्छ।
2. सिख धर्म के अनुसार सिखों के 10वें गुरु गोविन्द सिंह ने वर्ष 1699 में निहंग सिख का गठन किया था।
3. इन्हें अपने मार्शल युद्ध कौशल की वजह से धार्मिक तौर पर यौद्धा का दर्जा मिला हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है मगरमच्छ। सिख धर्म के अनुसार सिखों के 10वें गुरु गुरूगोविन्द सिंह ने वर्ष 1699 में निहंग सिख का गठन किया था। इन्हें अपने मार्शल युद्ध कौशल की वजह से धार्मिक तौर पर योद्धा का दर्जा मिला हुआ है। इस तरह तीनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

7. कोविड-19 की वजह से टीकाकरण में देरी

प्र. निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोविड-19 की वजह से दुनियाभर में लगभग 11.7 करोड़ बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया है।

(b) खसरा, मिजिल्स जीवाणु द्वारा फैलता है।

(c) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2018 में खसरा की वजह से 1,40,000 बच्चों की मौत हुई थी।

(d) खसरा और रुबेला अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी।

उत्तरः (b)

व्याख्याः संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि दुनियाभर में 11.7 करोड़ बच्चे खसरा के खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कई देशों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण टीकाकरण अभियान को रोक दिया है। विदित हो कि खसरा मिजिल्स विषाणु (Measless virus) द्वारा फैलता है। इस तरह कथन (b) गलत है। अतः उत्तर (b) होगा।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

- कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (STPI) से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराए के भुगतान से राहत प्रदान की है। इनमें से अधिकतर इकाइयाँ या तो टेक एमएसएमई या स्टार्टअप हैं।

क्या है एसटीपीआई

- विशेषज्ञों ने बताया कि यह पहल इन 60 एसटीपीआई केन्द्रों से संचालित लगभग 200 आईटी/आईटीईएस एमएसएमई को लाभ प्रदान करेगी। 1 मार्च से 30 जून 2020 के बीच 4 महीने की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराए में छूट का कुल अनुमानित खर्च करीब 5 करोड़ रुपए है। यह प्रयास लगभग 3000 आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों के बड़े हित में है, जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है।
- विदित हो कि भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसायटी है। इसकी स्थापना भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और वृद्धि करने के उद्देश्य से 1991 में की गई थी।
- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया परामर्शी, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग संसाधन रखता है। इन सेवाओं में नेटवर्क डिजाइन, प्रणाली एकीकरण, विविध क्षेत्रों में अप्रयुक्त नेटवर्क और सुविधाओं के संस्थापन, प्रचालन और उनका अनुरक्षण शामिल है। इसके देश भर में 60 केन्द्रों हैं। इन केन्द्रों के तहत स्थित इकाइयों को किराए में छूट प्रदान करने की पहल से कोविड-19 महामारी के कारण उभरी संकट की स्थिति में उद्योग को राहत मिलेगी।

एसटीपीआई के उद्देश्य

- सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी योग्य सेवाओं/ जैव-प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना।
- एसटीपी/ईएचटीपी योजना तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपी गई इसी तरह के अन्य योजनाओं को तैयार करके कार्यान्वित करके निर्यातकों को वैधानिक सेवाएँ प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित उद्योगों को सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी योग्य सेवाओं में विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाओं सहित आंकड़ा संचार सेवाएं प्रदान करना।
- आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में एक प्रेरक परिवेश बनाकर लघु, छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देना। ■

2. चित्रा जीन लैम्प-एन

- केरल में त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में कम कीमत वाली एक जांच किट तैयार की है। इस जांच किट का नाम 'चित्रा जीन लैम्प-एन' है। यह महज दो घंटे में कोविड-19 की पुष्टि कर सकती है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक काफी किफायती और तेज है तथा इसमें 100 प्रतिशत सटीकता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि अलाप्पुझा स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में किए गए परीक्षण में यह प्रदर्शित हुआ कि यह जांच किट आरटी-पीसीआर का उपयोग कर की गई जांच के नतीजों की तरह ही शत प्रतिशत समान और सटीक नतीजे देती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि नई जांच किट किफायती है क्योंकि प्रत्येक जांच की लागत 1,000 रुपये आएगी, जो मौजूदा जांच की न्यूनतम लागत से भी कम है।
- इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक मशीन पर एक ही साथ 30 नमूनों की जांच की जा सकती है। संक्रमण की पुष्टि करने वाली यह जांच किट, वायरल न्यूक्लिक एसिड का उपयोग कर सार्स-सीओवी-2 के एन जीन का पता लगाती है।
- वर्तमान में COVID-19 का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण की कीमत लगभग 15 से 45 लाख रुपये है, जबकि नए परीक्षण उपकरण की मात्रा केवल

2.5 लाख रुपये है। वर्तमान में इस्तेमाल की गई पीसीआर टेस्ट किट की कीमत लगभग 2,500 रुपये प्रति परीक्षण है, जबकि नवविकसित टेस्ट किट की कीमत केवल 1,000 रुपये प्रति टेस्ट है।

रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप-मध्यस्थता इजोटेर्मल प्रवर्धन (RT & LAMP) क्या है

- यह आरएनए के प्रवर्धन के लिए एक तकनीक है। इसका उपयोग वायरस का पता लगाने में किया जाता है। इस विधि में, वायरल आरएनए की एक डीएनए प्रति रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस द्वारा उत्पन्न की जाती है, और फिर डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए इजोटेर्मल प्रवर्धन किया जाता है। ■

3. त्रिशूर पूरम उत्सव

- इस वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था किंतु COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लाकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है परिणामतः केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। त्रिशूर पूरम उत्सव के लिये राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है जो कोचीन के महाराजा (1790-1805) थे और सक्थान थामपुरन के नाम से मशहूर थे।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान त्रिशूर पूरम उत्सव को सीमित तौर पर आयोजित किया गया था किंतु इस बार इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।
- यह केरल का वार्षिक उत्सव है जो वल्लुनावाडु क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज-सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। त्रिशूर पूरम में रात भर पटाखे चलाए जाते हैं, हाथियों की झांकियां निकाली जाती हैं तथा प्रसाद का वितरण किया जाता है।

महत्व

- त्रिशूर पूरम दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे केरल में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में स्थानीय ही नहीं बल्कि सैंकड़ों पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर (Vadakkunnathan Temple) में पूरम दिन (मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब मेडम (Medam) महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है।) पर आयोजित किया जाता है। यह सभी पूरम में सबसे बड़ा एवं सबसे प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय हैं कि इसमें दस मंदिरों को शामिल करके इस उत्सव को मनाया जाता है जिसमें परमेक्कावु, थिरुवमबाड़ी कनिमंगलम, करमकु, लल्लूर, चूरकोट्टुकरा, पनामुक्कमपल्ली, अय्यनथोले, चेम्बुकावु और नेथिलाकवु मंदिर शामिल हैं। उत्सव में 30 हाथियों को पूरी साज-सज्जा के साथ शामिल किया जाता है। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इलान्जिथारा मेलम नामक लाइव परफॉरमेंस भी आयोजित की जाती हैं। इस दौरान लगभग 250 कलाकार भाग लेते हैं। ■

4. विश्व धरोहर दिवस 2020

- विश्व धरोहर दिवस मानव विरासत, विविधता और एकीकृत निर्मित स्मारकों और विरासत स्थलों को बचाए रखने की जागरुकता और इन्हें बचाए रखने का प्रण है।
- विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय 'साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी' (Shared culture Shared heritage and Shared responsibility) है। आज जहां पूरी दुनिया COVID-19 महामारी से लड़ रही है, उस समय यह विषय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। COVID-19 के प्रकोप के कारण, संगठन ने इंटरनेट के माध्यम से विश्व विरासत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह इस बात को भी मानता है कि धरोहरों, स्थानों आदि के साथ विरासत जुड़ी हुई है या नहीं, इसका मूल्यांकन कई और विविध समूहों और समुदायों द्वारा किया जाना चाहिए।

विश्व धरोहर दिवसः इतिहास

- विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मानव विरासत को संरक्षित करने और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS) ने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया। इसे 1983 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण करना था।
- इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (प्लेटिनम) संगठन की स्थापना वेनिस चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों पर की गई थी, जिसे स्मारक और स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में भी जाना जाता है।

कैसे किया जाता है धरोहरों का संरक्षण

- किसी भी धरोहर को संरक्षित करने के लिए दो संगठनों अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ द्वारा आकलन किया जाता है। फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश की जाती है। समिति वर्ष में एक बार बैठती है और यह निर्णय लेती है कि किसी नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करना है या नहीं। विश्व विरासत स्थल समिति चयनित खास स्थानों, जैसे-वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि की देख-रेख यूनेस्को से सलाह करके करती है। ■

5. किसान रथ मोबाइल ऐप

- केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने किसान–रथ (Kisan Rath) नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण देश में तीन मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफी परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए यह ऐप लॉन्च किये हैं।
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण (Corona Virus) से पैदा हुए संकट की घड़ी में यह मोबाइल ऐप कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके लॉन्च होने के पहले ही दिन पांच लाख से अधिक वाहन उपलब्ध हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है और सभी राज्यों से भी किसानों के हित में ऐसे कदम उठाने को कहा है।

किसान रथ ऐप का फायदा

- केंद्र सरकार ने किसान रथ को लॉकडाउन की स्थिति में सब्जियों और फसलों की खरीद–बिक्री के लिए लॉन्च किया है, ताकि किसान आसानी से अपने सामान को बेच सकें और व्यापारी खरीद सकें। यह ऐप देशभर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी होगी। इसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियों और अनाज को बेच सकेंगे। इस ऐप के जरिए ट्रांसपोर्टर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ■

6. वैज्ञानिकों ने कोविड–19 के लिए तीन नये उत्परिवर्तन खोजा

- 17 अप्रैल 2020 को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) के वैज्ञानिकों ने COVID-19 वायरस के तीन नए उत्परिवर्तन खोजे हैं। इसके साथ GBRC COVID-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित करने वाली देश की पहली सरकारी प्रयोगशाला बन गई।
- वायरस के छह म्यूटेशन हैं जो अब तक पाए गए हैं। GBRC के वैज्ञानिकों ने तीन और नए उत्परिवर्तन पाए हैं, इसलिए अब तक वायरस के 9 म्यूटेशन पाए गए हैं। इसके अलावा, वैज्ञानिकों द्वारा उल्लेख किया गया है कि वायरस कई गुना तेजीसे बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस महीने में दो बार उत्परिवर्तन कर सकता है। वायरस के पूर्ण जीनोम अनुक्रमों को प्राप्त करने के लिए COVID-19 के अधिक नमूनों की आवश्यकता होती है।
- जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनोम के डीएन अनुक्रमों को खोजने के लिए किया जाता है।
- ICMR ने हाल ही में चमगादड़ों की दो प्रजातियों में COVID-19 वायरस पाया है। यह बताया गया है कि वायरस के उभरते उपभेदों को खोजने के लिए चमगादड़ की सक्रिय निगरानी भी आवश्यक है।

आइसीएमआर (ICMR)

- आइसीएमआर का फुल फॉर्म भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। यह भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के निर्माण, समन्वय और संदर्भ के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी है। यह भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त-पोषित है और दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ■

7. डोर टू डोर सर्वे के लिए 'असेस कोरोना' ऐप का उपयोग

- दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए नए असेस कोरोना (Assess Corona) ऐप का उपयोग करें। इससे एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।
- अधिकारियों का कहना है कि किसी व्यक्ति से जुड़े आंकड़े भौतिक रूप में एकत्र करने और उनके विश्लेषण में देरी एक बड़ी चुनौती है। इस ऐप की मदद से एकत्र किए गए आंकड़ों को तत्काल सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है और तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। इससे नियंत्रण केंद्रों को संबंधित क्षेत्र में एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल उपकरणों तथा चिकित्सा कर्मियों को जरूरत पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जल्दी फैसला होने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।
- विशेषज्ञों ने कहा कि जैसे ही सर्वाधिक प्रभावित इलाके (हॉटस्पॉट) की पहचान होती है और उस संबंध में निरूद्ध आदेश जारी किया जाता है, उनके सामने प्रमुख चुनौती घर-घर सर्वेक्षण के दौरान भौतिक रूप में आंकड़े एकत्र करने की होती है।
- ऐप-आधारित मूल्यांकन का पहला चरण दक्षिण दिल्ली में शुरू किया गया। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया के दौरान सर्वेक्षणकर्ता लोगों से उनकी हालिया यात्रा और संपर्क में आए लोगों के बारे में सवाल किया गया। इसके अलावा फ्लू जैसे लक्षण और सांस की तकलीफ के बारे में भी सवाल पूछा गया।
- दिल्ली सरकार जल्द ही घरों में पृथक रह रहे लोगों को इस मोबाइल ऐप के जरिए अपनी सेल्फी भेजने को कहेगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे घरों में पृथक रह रहे लोगों को विशिष्ट ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें। ■

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट' जारी की गयी। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नर्सों की स्थिति तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

2. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक संबंधों को एक नया मोड़ दिया है। हाल ही में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि अब वैश्विक संतुलन एशिया के हाथों में हो सकता है। इससे आप कितना सहमत है? चर्चा करें।

3. वर्तमान में कच्चे तेल के मूल्य में भारी गिरावट कोविड-19 महामारी का परिणाम है या फिर कुछ विकसित देशों की राजनीतिक चाल? चर्चा करें।

4. "किसी को समय से न्याय न मिलना भी एक बड़ा अन्याय है"। इस कथन से आप कितना सहमत है? चर्चा करें।

5. कोविड-19 महामारी ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि "जीवन वर्तमान को जीने की एक बेहतरीन कला है न कि भविष्य संवारने की मशीन"। उदाहरण सहित चर्चा करें।

6. धार्मिक नैतिकता और धर्म-निरपेक्ष नैतिकता के बीच अंतर का उल्लेख करते हुए यह बतायें कि एक सभ्य समाज के लिए इनमें से कौन सही है?

7. कोविड-19 महामारी के समय कलर कोडिंग का बढ़-चढ़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। कलर कोडिंग क्या है तथा यह महामारी को रोकने में किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

1. किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन-9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है?

   - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनस्ट्रेशन (NASA)

2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?

   - 142

3. कौन सा राज्य, देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य है?

   - गोवा

4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) ने सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस वैश्विक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सहयोग किया है?

   -यूनिसेफ

5. हाल ही में खबरों में रही 'एपीआई ग्रैविटी' से क्या पता किया जाता है?

   -तेल का घनत्व

6. गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया है?

   - टॉकबैक

7. हाल ही में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी के ऊपर 430 फीट लंबे पुल का उद्घाटन किया है?

   - अरुणाचल प्रदेश

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. अपने ज्ञान पर जरुरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है।

   - महात्मा गांधी

2. सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, एक ही मिट्टी से एक ही कर्मकार द्वारा बनाये गए और भले ही हम खुद को कितना भी धोखें में रख लें पर भगवान को जितना प्रिय एक सशक्त राजकुमार है उतना ही एक गरीब किसान।

   - प्लेटो

3. तुम्हे अन्दर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हे पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हे आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के आलावा कोई और गुरु नहीं है।

   - स्वामी विवेकानंद

4. शांति ताकत से नहीं कायम रखी जा सकती, ये केवल समझ से प्राप्त की जा सकती है।

   -अल्बर्ट आइंस्टीन

5. आपके जीवन में कितने साल हैं ये मायने नहीं रखता है लेकिन बचे हुए सालों में आपका जीवन कितना है ये मायने रखता है।

   -अब्राहम लिंकन

6. मनुष्य के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं: मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा।

   - अरस्तु

7. मजबूत दिमाग वाले विचारों पर, साधारण दिमाग वाले घटनाओं पर, जबकि निम्न दिमाग वाले लोगों पर चर्चा करते हैं।

   - सुकरात

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

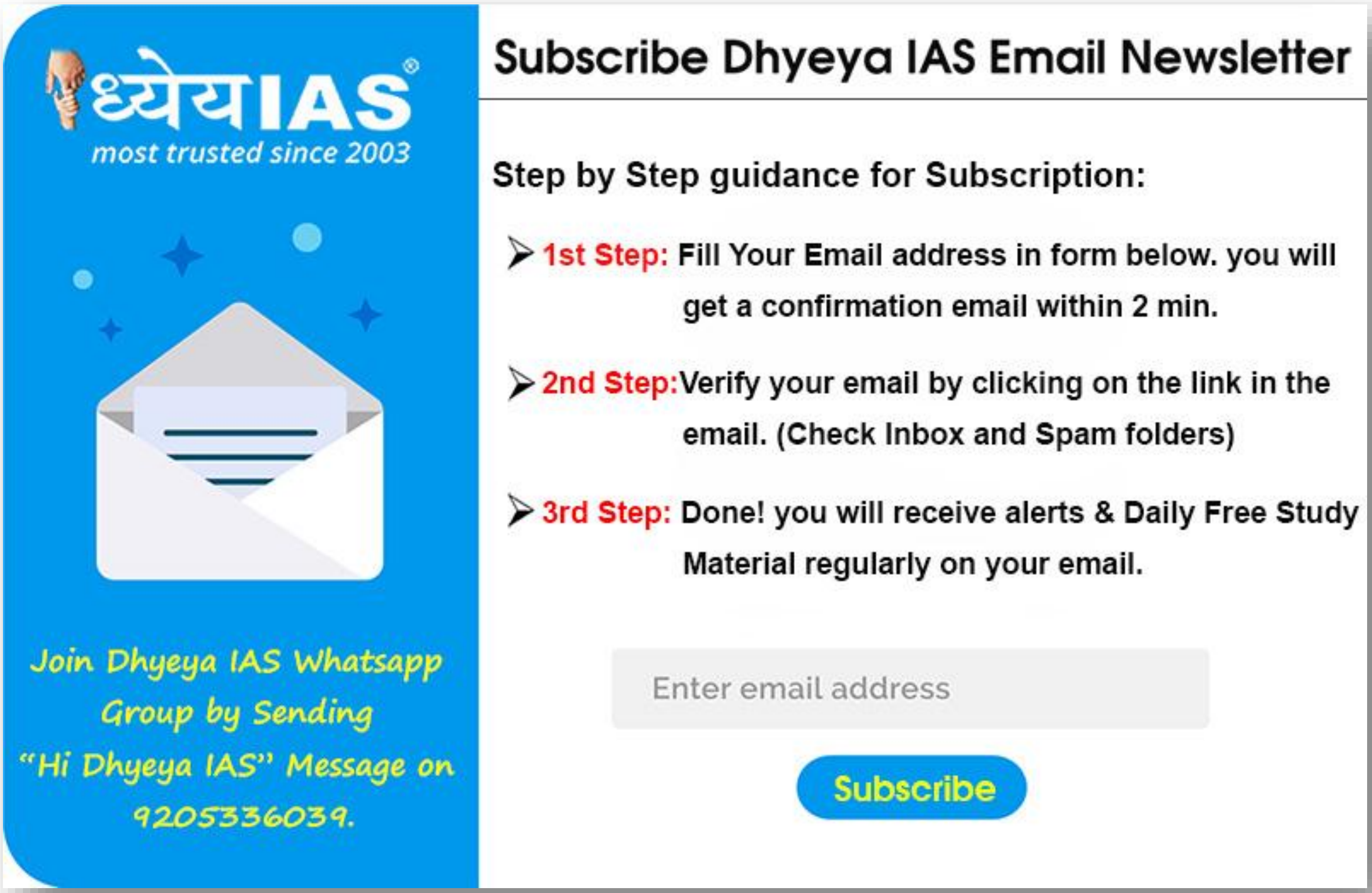

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009

Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400